Hindi/English Medium
निर्माण IAS

e-Magazine

योजना एवं कुरुक्षेत्र

नवम्बर, 2021

(जिस्ट)

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09

PH.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

Hindi/English Medium

निर्माण IAS

Give The Best ★ Take The Best

पढ़े उनसे जिन्होंने वास्तव में अधिकतम सफल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया

OUR FACULTIES

K.D. Sir
इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निबन्ध

Dharmendra Sir (Patanjali IAS)
एथिक्स

Dr. Rahees Singh Sir
इतिहास व अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Rajeev Ranjan Singh Sir
भारतीय राजव्यवस्था, गवर्नेंस

Sameem Anwar Sir
भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

Dr. Adarsh Sir
भारतीय राजव्यवस्था, गवर्नेंस आंतरिक सुरक्षा

Dr. Khursheed Alam Sir
नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

Shishir Sir
भारतीय अर्थव्यवस्था (Level-2)

Gautam Anand Sir
भारतीय समाज व सामाजिक न्याय

Dr. Raj Shekhar Sir
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

D.P.N. Singh Sir
सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

Lokesh Tripathi Sir
भारतीय अर्थव्यवस्था (Level-1)

सामान्य अध्ययन

फाउण्डेशन बैच 2022-23

9 am Morning Batch

भारतीय राजव्यवस्था के साथ कक्षा प्रारम्भ...

By: Rajeev Ranjan Sir

04 January | 6:00 PM

21 January

English Medium
Exclusive Batch - 2022-23

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09
PH.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797

स्थानीय शासन में जन भागीदारी

- भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में पंचायती राज संस्थानों की अहम भूमिका रही है। संविधान के 73वें संशोधन के जरिए इन संस्थानों के लिए मजबूत बुनियाद तैयार की गई है।

ग्राम सभा का कामकाज

- ग्राम सभा के तहत, गांवों की निर्णय प्रक्रिया में वहां के नागरिकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। यह नागरिकों के लिए सार्वजनिक मंच है जहां वे अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बता सकते हैं।
- ग्राम सभा के कामकाज में भी चुनौतियां देखने को मिली हैं। यहां नियमितता और पारदर्शिता का अभाव नजर आता है।
- न्यूनतम भागीदारी, ग्राम सभा की बैठकों में अनियमितता, बेहतर कार्य सूची का अभाव जैसी कमियों के कारण ग्राम सभा का संचालन प्रभावकारी तरीके से नहीं हो पाता है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, खास तौर पर सरपंच अपने अधिकारों का मनमाना इस्तेमाल करते हैं।

अनुच्छेद 243:

- *ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एक गांव से संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर एक निकाय के रूप में परिभाषित करता है।*

अनुच्छेद 243ए:

- *ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है जो राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा प्रदान करे।*
- *इस तरह, अक्सर ग्राम सभा की भूमिका महज एक सांकेतिक मंच के तौर पर सिमट कर रह जाती है।*

राज्यों में ग्राम सभा

- कर्नाटक, केरल, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ग्राम पंचायतों के बड़े आकार को देखते हुए यहाँ की पंचायतों में वॉर्ड सभा आदि का अतिरिक्त ढांचा भी तैयार किया गया। इनमें ग्राम सभा की बैठक से पहले वॉर्ड सभा की बैठक का नियम तय किया गया है।
- पंचायती राज कानून के तहत, कुछ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायतों से जुड़े निश्चित वोटों के आधार पर ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। इनमें छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, लक्षद्वीप शामिल हैं।
- ग्राम सभा के अधिकारों और कामकाज के बारे में फैसला लेने के लिए राज्यों को अधिकृत किया गया है। संबंधित राज्यों के पंचायती राज कानूनों के अनुसार बैठकों की निर्धारित अनिवार्य संख्या के अलावा, राष्ट्रीय महत्व के दिनों मसलन गणतंत्र दिवस, अंबेडकर जंयती, मजदूर दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती पर भी ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन किया जाता है।
- पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को इन विशेष बैठकों का बेहतर इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसके अलावा, विभिन्न तरह के अभियानों जैसे संविधान दिवस, कोरोना जागरूकता अभियान, फिट इंडिया अभियान, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस आदि को ध्यान में रखते हुए भी ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाता है।
- ग्राम सभाओं का नियमित तौर पर आयोजन बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे ग्राम सभा जैसे संस्थान में ग्रामीण लोगों का भरोसा बढ़ता है।
- कई राज्यों में ग्रामीणों और इससे जुड़े महत्वपूर्ण पक्षों जैसे- निर्वाचित प्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, विशेषज्ञों की सभाओं में सीमित भागीदारी देखी गई है। ग्राम सभा को प्रभावी बनाने में यह एक बड़ी बाधा है।

आवश्यकता और प्रासंगिकता

- ग्राम सभा की परिकल्पना एक विशिष्ट संस्थान के तौर पर की गई थी, ताकि नागरिक जमीनी स्तर पर मौजूद समस्याओं को प्रमुखता से पेश कर सकें और संभावित समाधानों पर आम-सहमति बना सकें। ग्राम सभा के फैसले खुले, पारदर्शी और व्यापक स्वीकार्यता वाले होते हैं।
- भारत सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, जल आपूर्ति और स्वच्छता से जुड़ी कई योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए

आम नागरिकों की एकता और उनकी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

- ग्राम सभा इसके लिए आदर्श मंच मुहैया कराती है, जिसके जरिये नागरिकों से सीधा संवाद कर इन योजनाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है।

डाडेरा ग्राम पंचायत, अयोध्या, उत्तर प्रदेश

- पिछले कुछ साल में कुछ राज्यों ने ग्राम सभा में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देकर इसका बेहतर इस्तेमाल सुनिश्चित किया है। साथ ही, स्थानीय समस्याओं से निपटने में सफलता हासिल की है।
- साल 2019 में प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोगों ने सामान्य जल और बारिश के पानी के संरक्षण की जरूरत महसूस की। नागरिकों ने उपेक्षित पड़े कुंओं, गंदे पानी, नालियों आदि के बेहतर प्रबंधन के लिए काम शुरू किया।
- ग्राम पंचायत में जल शक्ति अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत कई कदम उठाए गए, मसलन तालाब की खुदाई, गंदे पानी का प्रबंधन, सार्वजनिक भवनों में बारिश के पानी का प्रबंधन आदि।
- इन उपायों से न सिर्फ गांव की कृषि संबंधी पानी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि घटते भूजल स्तर को भी बेहतर किया जा सका।
- ग्राम पंचायतों ने तालाब की खुदाई के दौरान जमा हुई मिट्टी की बिक्री की और तालाब में मछली और बत्तख का पालन भी शुरू हुआ।
- गांव के लोगों द्वारा ग्राम सभा के माध्यम से एक समस्या पर विचार किया गया और इसके समाधान के लिए आम-सहमति तैयार की गई। इस तरह की पहल से राजस्व का नया स्रोत भी पैदा हुआ और इसकी वजह से ग्राम पंचायत का भी सशक्तीकरण हुआ।
- इस फैसले से ग्राम पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली और ग्रामीणों के लिए रोजगार के स्रोत तैयार किए जा सके।

ग्राम सभाओं का कामकाज प्रभावी बनाने के उपाय

- वित्त आयोग द्वारा आवंटित समग्र अनुदान का इस्तेमाल पंचायतों से जुड़ी विभिन्न जरूरतों के लिए किया जा सकता है।
- पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में मौजूद पंचायती राज से जुड़े संस्थानों के वित्त, कामकाज आदि के विकेंद्रीकरण की दिशा में काम कर रहा है।
- मंत्रालय का मकसद ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीकरण के साथ-साथ ग्राम सभाओं का सशक्तीकरण भी है। इसके तहत ग्राम सभाओं को जरूरी संसाधन मुहैया कराए गए हैं, ताकि वे सही ढंग से अपना काम कर सकें।
- पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम सभाओं की भूमिका को पहचानते हुए राज्य स्तर पर मौजूद पंचायती राज विभागों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की है, ताकि ग्राम पंचायतों के लिए जमीनी स्तर पर मौजूद चुनौतियों को समझा जा सके।
- इस सिलसिले में राज्यों की चुनौतियों को देखते हुए राज्य/केंद्रशासित प्रदेशों को ये सुझाव पेश किए गए हैं:

1. ग्राम सभाओं का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना:

- ग्राम पंचायतों को नियमित तौर पर ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन इससे जुडी प्रशासनिक जरूरतों आदि के आधार पर किया जा सकता है।

2. एजेंडा/कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करना और उसका वितरण:

- ग्राम सभा के एजेंडे में, आधारभूत संरचना से जुड़े कार्यों के चुनाव/मंजूरी/ प्रगति/निगरानी और गांव-स्तर के कर्मियों के प्रदर्शन की समीक्षा भी शामिल होनी चाहिए।

3. सालाना कैलेंडर तैयार करना:

- ग्राम सभाओं की बैठक के लिए राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए।
- सालाना कैलेंडर होने से ग्राम सभाओं में गांव के लोगों की भागीदारी बढेगी और पंचायतों की बैठकों के लिए बेहतर ढंग से कार्यक्रम तैयार किए जा सकेंगे।

4. बेहतर ढंग से कार्यक्रम तैयार करना:

- ग्राम सभाओं की बैठकों को वैकल्पिक तौर पर बुलाया जाना चाहिए, ताकि किसी खास दिन सिर्फ चुनिंदा समूह (क्लस्टर) के ग्राम पंचायतों की बैठक हो सके।

5. बैठक के लिए अनुकूल समय:

- ग्राम सभाओं की बैठक का समय ग्रामीण आबादी के लिए अनुकूल होना चाहिए, ताकि बड़ी संख्या में लोग इसमें पहुंच सकें।

6. प्रथम और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों की मौजदगी:

- जिला प्रशासन को ग्राम सभाओं की सभी बैठकों में प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के अधिकारियों की मौजूदगी सुनिश्चित करनी चाहिए।

7. ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाना:

- ग्राम सभाओं में सभी सक्षम नागरिकों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ग्राम सभाओं की बैठक में कम से कम 10 प्रतिशत

महिला और 30 प्रतिशत पुरुषों की मौजूदगी जरूरी है।

- ग्राम सभा को लेकर लोगों की जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, आशा कार्यकताओं, रोजगार सहायकों आदि की सेवाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
- ग्राम सभाओं में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए मेडिकल जांच, तकनीक से जुड़ी ग्रामीण परियोजनाओं का इस्तेमाल, स्कूलों/स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा जैसी गतिविधियों का भी सहारा लिया जा सकता है।

8. वॉर्ड सदस्यों/निर्वाचित सदस्यों को प्रोत्साहन:

- ग्राम पंचायतों के सभी सदस्यों/निर्वाचित सदस्यों को उपसमितियों का सदस्य बनाया जाना चाहिए। साथ ही, हर वॉर्ड सदस्य को दो से ज्यादा उपसमितियों का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए।
- ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किए जाने वाले कार्यक्रमों और योजनाओं को सुचारु रूप से चलाने और उनकी निगरानी के लिए स्थायी उपसमिति बनाना भी जरूरी है।
- ज्यादातर राज्यों में ग्राम पंचायतों ने अलग-अलग तरह की स्थायी समितियां बनाई हैं जिनमें वित्तीय और नियोजन स्थायी समिति, शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य समिति, कृषि और पशु संसाधन विकास स्थायी समिति, उद्योग और आधारभूत संरचना स्थायी समिति, महिला, बाल विकास स्थायी समिति और सामाजिक कल्याण स्थायी समिति शामिल हैं।

- पंचायतों और उनके कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की भावना विकसित करने में ग्राम सभा बेहतर माध्यम है।
- यह दीर्घकालिक अवधि में, ग्राम पंचायतों को ग्रामीण इलाकों के सामाजिक-आर्थिक विकास का इंजन बना सकता है।
- ग्राम सभाओं की सक्रिय भूमिका से भारत को सतत विकास के लक्ष्यों को भी हासिल करने में मदद मिलेगी और ग्राम पंचायत स्तर पर इस दिशा में काम करना मुमकिन होगा।
- पंचायती राज मंत्रालय एकीकृत और रियल-टाइम ऑनलाइन प्रणाली विकसित करने की प्रक्रिया में है। यह प्रणाली न सिर्फ ग्राम सभाओं के लिए प्रभावी कार्यक्रम तय करेगी, बल्कि फैसले लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिकों को सुझाव भी देगी।
- लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर ग्राम सभाएं न सिर्फ गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करेंगी, बल्कि इनसे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक स्तर पर बड़ा बदलाव का मार्ग भी प्रशस्त होगा।

स्वामित्व योजना

- विश्व में आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य के साथ चलाई जाने वाली अधिकतर आर्थिक गतिविधियों के लिए भूमि आवश्यक संसाधन है। इसलिए भूमि संसाधनों का प्रबंधन किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है।
- बैंक भू-संपत्ति को वित्तीय संपत्ति मानकर इसके बदले ऋण तथा दूसरी वित्तीय सहायता देते हैं लेकिन कानूनी दस्तावेज नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति का स्वामी लाभ नहीं उठा पाता।
- इन ग्रामीणों के पास गैर-संस्थागत ऋणदाताओं से कर्ज लेने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं रह जाता और वे ऋणदाता उनसे ऊंची दर पर ब्याज वसूल कर सकते हैं।
- ग्रामीण भारत में आवासीय भूमि के अधिकारों के रिकॉर्ड का सांख्यिकी अनुमान प्रदान करने वाले सर्वेक्षण बहुत कम हैं क्योंकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अथवा भारतीय मानव विकास सर्वेक्षण जैसे सर्वेक्षणों में या तो कृषि भूमि ली जाती है अथवा आबादी भूमि को अलग किए बगैर समूची भूमि शामिल की जाती है।
- भारत में यह अहम बात है क्योंकि एक औसत परिवार की कुल संपत्तियों में से 77 प्रतिशत रियल एस्टेट (जिसमें आवासीय इमारतें, कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों के लिए प्रयुक्त इमारतें, मनोरंजक सुविधाओं का निर्माण तथा ग्रामीण एवं शहरी भूमि शामिल होती हैं) के रूप में होती हैं।
- यह आंकड़ा अमेरिका में 40 प्रतिशत, चीन के लिए 60 प्रतिशत, थाईलैंड में 50 प्रतिशत और ब्रिटेन में केवल 35 प्रतिशत है।
- भारत में ग्रामीण आबादी वाले इलाकों में अधिकार के रिकॉर्ड नहीं होने के कारण भूमि प्रशासन का स्तर कम रहा है, संपत्तियों का स्वामित्व अनुमानों पर आधारित होता है, संपत्ति विवाद लंबे समय से अटके हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि बाजार में तरलता बहुत कम है।

स्वामित्व योजना

- भारत के 6.62 लाख गांवों में आधुनिकतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण परिवार के मालिकों को संपत्ति कार्ड के रूप में अधिकार के रिकॉर्ड प्रदान

करने की आवश्यकता महसूस हुई, जिस कारण स्वामित्व योजना का जन्म हुआ।

- योजना का लक्ष्य गांवों में ग्रामीण आबादी में मकान रखने वाले ग्रामीण परिवारों के मालिकों को अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति स्वामियों को संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। इससे ऋण तथा अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए ग्रामीण आवासीय संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में मदद मिलेगी।
- स्वामित्व योजना के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं:
  - ग्रामीण भारत के नागरिकों द्वारा संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में इस्तेमाल।
  - ग्रामीण नियोजन के लिए सटीक भूमि रिकॉर्ड तैयार करना।
  - ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत भूमि प्रमाणन समाधान प्रदान करना।
  - संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी का साधन बनना।
  - संपत्ति कर तय करने में मदद प्राप्त करना।
  - सर्वेक्षण के लिए बुनियादी ढांचे तथा जीआईएस मानचित्र तैयार करना, जिनका उपयोग कोई भी विभाग अथवा एजेंसी कर सकेंगे।
- स्वामित्व योजना में बहुत बड़े क्षेत्र का एकदम सटीक सर्वेक्षण बहुत कम समय में करने के लिए सर्वे ग्रेड ड्रोन्स तथा कोर्स नेटवर्क (कंटिन्यूअसली ऑपरेटेड रेफरेंस स्टेशन्स) का प्रयोग किया जाता है।
- उच्च रिजॉल्यूशन युक्त और सटीक चित्र आधारित मानचित्रों से उन क्षेत्रों में संपत्ति स्वामित्व के सबसे टिकाऊ रिकॉर्ड तैयार करने में मदद मिलती है, जिन क्षेत्रों में पीढ़ी दर पीढ़ी राजस्व रिकॉर्ड नहीं होते हैं।
- ऐसे सटीक चित्र आधारित मानचित्र जमीन पर भौतिक माप एवं भूमि खंडों को मापने की तुलना में बहुत कम समय में भूमि का स्पष्ट सीमांकन उपलब्ध करा देते हैं।
- इस योजना का पायलट फेज (परीक्षण चरण) 24 अप्रैल 2020 को छह राज्यों- हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आरंभ किया गया। बाद में पंजाब तथा राजस्थान के एक सीमावर्ती जिले के गांवों एवं आंध्र प्रदेश के कुछ गांवों को भी क्रियान्वयन के परीक्षण चरण में जोड़ा गया।
- 24 अप्रैल 2021 को सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में यह योजना आरंभ कर दी गई। अभी तक 28 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपने यहां स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन के लिए भारतीय सर्वेक्षण के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तमिलनाडु परीक्षण गांवों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के अंतिम चरण में है।
- भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना-2011 (एसईसीसी-2011) पर आधारित अनुमानों के अनुसार योजना से लगभग 13.13 करोड़ परिवारों को लाभ मिलने की संभावना है।

आगे की राह

- सटीक भूमि रिकॉर्ड एवं जीआईएस मानचित्र तैयार होने से पंचायतों को बेहतर ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में मदद मिलेगी।
- संपत्तियों के सटीक सीमांकन एवं पारदर्शी भूमि स्वामित्व अधिकार के कारण ग्राम पंचायतें उन राज्यों में संपत्ति कर का निर्धारण तथा संग्रह बेहतर ढंग से कर सकेंगी, जहां उन्हें यह कार्य दिया गया है।
- योजना ने देश में ड्रोन व्यवस्था को भी रफ्तार दी है। इसे ड्रोन विनिर्माण, पायलट प्रशिक्षण तथा ड्रोन को सर्विस मॉडल के रूप में प्रयोग कर बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कुशल मानवशक्ति की आवश्यकताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और स्टार्टअप तथा एमएसएमई के लिए रास्ते खुलेंगे।
- इस प्रकार स्वामित्व योजना का लक्ष्य गांवों एवं उनके निवासियों के सशक्तीकरण के माध्यम से ग्राम पंचायत का सर्वांगीण विकास है, जिससे अंत में ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा।

ग्राम पंचायत विकास योजनाएं

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि स्थानीय मामलों में समुदाय की अधिक भागीदारी से सरकार द्वारा विशेष रूप से समाज में गरीब और वंचित समूहों के जीवन में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- 73वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण भारत के लिए विकेन्द्रीकृत स्थानीय शासन का औपचारिक त्रिस्तरीय ढांचा तैयार किया है जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य सुविधाविहीन समुदायों को शासन में भागीदार के रूप में शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243जी पंचायत प्रणाली की समावेशी, समुदाय संचालित और समग्र नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को अनिवार्य करता है, जिससे ये संस्थान स्थानीय स्वशासन निकायों के रूप में विकसित होते हैं।

- पंचायती राज मंत्रालय पंचायत के पर्याप्त प्राधिकार और अधिकार देने के लिए संवैधानिक अधिदेश की भावना का पालन करते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं की तैयारी और कार्यान्वयन के संबंध में, उन्हें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाता है।

ग्राम पंचायत विकास योजना-जीपीडीपी

- वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान व्यापक और सम्मिलित विकास योजना के वाहक के रूप में ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को संस्थागत रूप दिया गया था।
- यह योजना प्रक्रिया गांव के समुदाय के सदस्यों द्वारा विकेन्द्रीकृत नियोजन की सुविधा प्रदान करती है।
- भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं के साथ-साथ 'स्वयं के स्रोतों से राजस्व' के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का अभिसरण, ग्राम पंचायतों को ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी आवश्यकता-आधारित विकास योजनाएं बनाने का अवसर प्रदान करता है। अनुसूची के पारंपरिक निकायों को ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदान की सिफारिश की है।
- सुशासन और समावेशी सामाजिक विकास के लक्ष्य के अनुरूप पंचायतों को इस विशाल अखंडित निधि प्रवाह ने सभी राज्यों में ग्राम स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना आवश्यक किया है।

ग्राम पंचायत विकास योजना के व्यापक उद्देश्य

- ग्राम पंचायतों द्वारा शासित ग्रामीण क्षेत्रों के एकीकृत और समावेशी विकास को सुनिश्चित करना, जो न केवल बुनियादी ढांचे के अनुरूप विकास के लिए बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सामुदायिक विकास के लिए भी है।
- सहभागी नियोजन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय को शामिल करना और सक्षम बनाना। स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों की पहचान सुनिश्चित करना और सहभागी नियोजन और अभिसरण के माध्यम से सभी समुदायों की स्थानीय जरूरतों को पूरा करना।
- बुनियादी सामाजिक आवश्यकताओं के प्रावधान और गरिमामय जीवन के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य वंचित समुदायों, अन्य पिछड़े समुदायों, महिलाओं, बच्चों, कमजोर समूहों और दिव्यांगों का समावेशन और कल्याण सुनिश्चित करना।
- स्थानीय क्षेत्रों में सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता और प्रभावकारिता में सुधार करना। स्थानीय स्तर पर जवाबदेही उपायों को मजबूत करना।

ग्राम पंचायत विकास योजनाओं और क्षेत्रों का अभिसरण

- ग्राम पंचायत विकास योजना नियोजन प्रक्रिया व्यापक होनी चाहिए जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित योजनाओं के साथ अभिसरण शामिल है।
- राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर प्रमुख योजनाओं के प्रभावी और कुशल कार्यान्वयन में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
- वित्त आयोग द्वारा ग्राम पंचायतों को धन के वितरण के संदर्भ में पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी को एक अनिवार्य गतिविधि बना दिया है।
- मंत्रालय ने 2015 में आदर्श ग्राम पंचायत विकास योजना दिशानिर्देश तैयार किए थे और बाद में, नए पुनर्गठित व्यापक ग्राम पंचायत विकास योजना दिशानिर्देश 2018 लागू किए गए थे।
- वर्षों से, ग्राम पंचायतें, अधिक अभिसरण और सहभागी योजनाएं तैयार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों की विभिन्न योजनाओं का उपयोग कर रही हैं।
- अध्ययनों के अनुसार सार्वजनिक एजेंसियों और उपलब्ध संसाधनों के बीच सहयोग, नागरिकों के लिए सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाने में 'सहयोगात्मक' परिणाम दे सकता है।
- केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयासों और संबंधित आदेशों के बावजूद, कई केंद्र प्रायोजित योजनाओं का, ग्राम पंचायत विकास योजना में अभिसरण वर्षों से परिलक्षित नहीं होता है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए क्षेत्रीय निधि आवंटन कुछ क्षेत्रों तक सीमित है जहां केंद्रीय या राज्य वित्त आयोग के फंड और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) जैसी योजनाओं से मुख्य वित्त पोषण प्रदान किया जाता है।
- सड़क निर्माण, पानी और स्वच्छता के क्षेत्रों में आवंटन का प्रतिशत, अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ग्राम पंचायतों को इन क्षेत्रों से संबंधित अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों से उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण की अधिक आवश्यकता है।
- मनरेगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, पोषण आदि जैसी ग्राम पंचायत स्तर पर लागू की जाने वाली सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के दिशानिर्देश स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत स्तर पर योजना तैयार करने पर जोर देते हैं।
- ग्राम पंचायत विकास योजना एक एकीकृत योजना दस्तावेज

है, इसलिए आदर्श रूप से पंचायत के सभी पहलुओं में इसके समग्र दृष्टिकोण को शामिल करना चाहिए।

- इस तरह की एक एकीकृत योजना विभिन्न क्षेत्रों से अधिक धन को अवशोषित करने और स्थानीय संसाधन जुटाने में मदद करती है, जिससे सेवा वितरण को सुधारने में मदद मिलती है।
- ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से विभिन्न संबंधित विभागों की सभी योजनाओं और कार्यक्रमों के अभिसरण से इनके दोहराव से बचा जा सकेगा, वित्तीय बोझ कम होगा और वांछित परिणामों की उपलब्धि में तेजी आएगी।

क्षमता निर्माण की आवश्यकता

- स्थानीय लोकतंत्र और लोगों के नेतृत्व में विकास को मजबूत करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकार लगातार नया करने और हितधारकों के एक बड़े वर्ग को नियोजन तथा विकास प्रक्रिया में शामिल करने का प्रयास कर रही हैं।
- मंत्रालय 2018 में शुरू किए गए राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की अपनी प्रमुख योजना के माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर बहुत जोर देता है।
- 2018 से, ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए बड़े पैमाने पर ये प्रयास देश भर में सालाना जन योजना अभियान (सबकी योजना सबका विकास) के माध्यम से मिशन मोड में शुरू किए गए हैं।
- यह अभियान विभिन्न संबद्ध मंत्रालयों/विभागों के अधिकारियों के सक्रिय सहयोग से विशेष ग्राम सभाओं के माध्यम से ग्राम पंचायतों द्वारा नियोजन के लिए एक गहन और संरचित प्रयास है।

इब्राहिमपुर, तेलंगाना की केस स्टडी

- *इब्राहिमपुर गांव में हाल में ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम शुल्क के साथ सुरक्षित पेयजल, शत-प्रतिशत स्वच्छता, जल संरक्षण, जैविक खाद, मच्छर मुक्त गांव और गांव के घरों के लिए सोलर लाइट जैसी सेवाएं उत्कृष्ट तरीके से प्रदान करने के प्रयासों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं।*
- *सिद्दीपेट जिला मुख्यालय से करीब लगभग 25 किमी दूर स्थित इस गांव की आबादी 1,119 है।*
- *इस ग्राम पंचायत ने पिछले कुछ वर्षों में विकास गतिविधियों के लिए निर्मल पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार सहित कई पुरस्कार जीते हैं। कुछ साल पहले तक, इस ग्राम पंचायत में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं।*
- *यहां स्वास्थ्य, स्वच्छता, पेयजल जैसे क्षेत्रों में विशेष विकास नहीं हुआ था, लेकिन व्यापक जागरूकता के साथ-साथ युवाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और सक्रिय ग्राम सभाओं की गहन सामुदायिक भागीदारी के कारण, इब्राहिमपुर सतत विकास के लिए एक आदर्श गांव में तब्दील हो गया।*

- व्यापक नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के माध्यम से विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों को एक सर्वोत्तम विकल्प के रूप में पहचाना जा रहा है।
- प्रभावी स्थानीय शासन न केवल सरकारी संस्थानों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर शासन करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है बल्कि स्थानीय समुदायों और स्थानीय अधिकारियों के बीच सहयोग और सामूहिक कार्रवाई भी करता है। राष्ट्र के शासन में लोगों की भागीदारी लोकतंत्र का सार है। देश भर में 95 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतें, ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार कर रही हैं।
- अधिक संधारणीय और समावेशी ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए पंचायती राज संस्थाओं- स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से निरंतर प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, हितधारकों के क्षमता विकास सहित मौजूदा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए. मंत्रालय ने कई पहल की हैं।
- इस प्रक्रिया के तहत गरीबी उन्मूलन योजनाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना में एकीकृत करने के लिए विशेष प्रावधान शुरू किया गया है।
- विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में अभिसरण और समुदाय-आधारित संगठनों के एकीकरण के साथ, संबंधित मंत्रालयों के लोकतांत्रिक संस्थानों के साथ मिलकर विकास योजनाओं के जन-केंद्रित दृष्टिकोण से भौतिक, वित्तीय, सामाजिक और पूंजी निर्माण संबंधी तथा ग्रामीण स्तर पर दीर्घकालिक सतत विकास कार्यों के नेतृत्व से निश्चय ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।

सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण

- विश्व के नेताओं के बीच सितम्बर, 2015 में स्थायी विकास लक्ष्यों पर सहमति बनी थी ताकि विश्व में ऊर्जा भरकर गरीबी और असमानता में जबर्दस्त कमी लाकर आने वाले 15 वर्ष की प्राथमिकताएं और कार्य-योजनाएं बनाई जा सकें।
- इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का उद्देश्य गरीबी खत्म करके असमानता को हमेशा के लिए मिटा देना है जिससे दुनिया के सामने मुंह बाए खड़ी पर्यावरण-संबंधी चुनौतियों का टिकाऊ और स्थायी समाधान निकाला जा सके।
- इन प्रयासों के अंतर्गत विकास के लिए डेटा क्रान्ति ने गति पकड़ ली है और इससे वैश्विक संसाधनों का दोहन करके आवश्यकता का पता लगाकर उनकी पूर्ति के लिए अधिक विकास का लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा।
- डेटा क्रान्ति की मदद से वैश्विक लक्ष्यों को 2030 तक पूरा करने की आशा बन जाएगी और इसके लिए डेटा-चालित निर्णय प्रक्रिया, तथ्यों पर आधारित नीतियां और विकास कार्यों की साझी जवाबदेही तथा सरकार और अन्य हितार्थियों की ओर से समुचित निवेश को बढ़ावा देना होगा।

डेटा क्रान्ति

- *डेटा क्रान्ति का अर्थ है डेटा के प्रयोग से चलाए जाने वाले किसी जटिल विकास एजेंडा की जरूरत के हिसाब से आवश्यक क्रान्ति लाने वाले कार्य।*
- *इसके तहत डेटा तैयार करने, डेटा एक्सेस करने और उसे प्रयोग करने में क्रांतिकारी सुधार लाने की प्रक्रिया शामिल है।*
- *कई देशों में डेटा जुटाने का काम उस देश की सरकार की एजेंसी करती है और इसके लिए एजेंसी जनसंख्या के पूर्व-निर्धारित वर्ग से आंकड़े प्राप्त करती है जिनका जटिल वैज्ञानिक विधियों से विश्लेषण किया जाता है और राष्ट्रीय सकल अनुमान लगाए जाते हैं।*
- *आंकड़े एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने में अत्यधिक विशेषज्ञता की जरूरत होती है और इसीलिए अधिकांश नागरिक और सरकारी अधिकारियों को इस कार्य से दूर कर दिया गया है, इनमें से कुछ तो बस रिपोर्ट को पढ़ने तक की ही योग्यता रखते हैं।*

- पंचायत स्तर पर डेटा क्रान्ति से समुदाय ऐसे लक्ष्यों और संकेतकों की पहचान करके उन्हें डिजाइन कर सकता है जो उन लोगों के संदर्भ में विशेष महत्व रखते हैं। इससे ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो जाता है जिसकी मदद से लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में उस समुदाय की प्रगति आंकी जा सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा सितम्बर, 2015 में पारित क्रांतिकारी एजेंडा-2030 के तहत पृथ्वी के निवासियों और पृथ्वी ग्रह की सुरक्षा और सभी के लिए समृद्धि का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम बनाया गया था।
- ये लक्ष्य वैश्विक हैं और सभी पर लागू होते हैं इसलिए सभी देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी प्राथमिकताएं तय करके इस एजेंडे की भावना के अनुरूप अपनी राष्ट्रीय और स्थानीय जरूरतों के मुताबिक स्थानीय स्थायी विकास लक्ष्य निर्धारित कर लें।
- समाज की बेहतरी और जरूरी बदलाव के जरिये स्थायी विकास लक्ष्यों की चुनौती से निपटने के तरीके समझ में आते हैं और स्थायी विकास लक्ष्यों, देश की नीतियों, देश की पंचवर्षीय योजना और स्थानीय निकाय विकास योजनाओ में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बनाने की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सकती है।

स्थानीय निकाय स्तर पर डेटा क्रांति को सफल बनाने के उपाय

1. आधार तैयार करें

- यह जरूरी है कि स्थानीय डेटा क्रान्ति की प्रक्रिया के लिए आधार तैयार किया जाए-
  - समुदाय (लोगों) और विभिन्न विकास अधिकारियों के साथ मजबूत संचार चैनल विकसित किए जाएं।
  - सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा के लिए सामुदायिक बैठकें आयोजित करने की परम्परा चलाएं ताकि लोग धीरे-धीरे अपनी झिझक छोड़कर सहज भाव से अपने परेशानी बताने लगे।
  - विभिन्न स्तरों के सरकारी अधिकारियों से मजबूत नजदीकी रिश्तें बनाएं।

2. समुदाय को संगठित करें

- लोगों में प्रभाव रखने वाले सामुदायिक नेताओं और ऐसे स्वयंसेवकों की पहचान कर लें जो पंचायत स्तर की डेटा-पहल में स्थानीय निकाय के अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने को राजी हो सकते हैं।

3. क्षमता निर्माण करें

- स्थायी विकास लक्ष्यों के बारे में प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

स्मार्टफोन को डेटा जुटाने के उपकरण के रूप में प्रयोग करने का प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

4. डेटा एकत्र करें

- समुदाय ने जिन लक्ष्यों और संकेतकों की समीक्षा की है उनके आधार पर सर्वे विकसित करें।
- डेटा एकत्रीकरण के बारे में महत्वपूर्ण बात है कि कोशिश करके सुनिश्चित किया जाए कि हर संबद्ध व्यक्ति (प्रत्येक परिवार) से जानकारी जुटायी जाए।

5. डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया पर प्राप्त फीडबैक

- समुदाय डेटा एकत्रीकरण प्रक्रिया से संतुष्ट और आश्वस्त होना चाहिए।

6. लोगों के साथ मिलकर विश्लेषण करें

- सामुदायिक डेटा का विश्लेषण काफी आसान होता है. क्योंकि यह व्यक्ति के बारे में या कम-से-कम अधिकतर परिवारों के बारे में होता है। डेटा से उत्पन्न होने वाले विचारों को इकट्ठा करके उन पर मिलकर विचार करने से समुदाय आंकड़ों के उद्देश्य को बेहतर तरीके से समझ पाता है जिससे वे उन विचारों के समर्थन में चर्चा के मुद्दे तैयार कर पाते हैं और चुनौतियों को भी अच्छे ढंग से समझ लेते हैं।

7. विकास के लिए संपर्क स्थापित करें

- विचारों के आधार पता चलता है कि स्थानीय निकायों के अधिकांश अधिकारियों के पास लोगों के लिए विकास गतिविधियां लागू करने के संसाधन नहीं होते।

डेटा क्रान्ति : संकेतकों की भूमिका

- स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थायी विकास लक्ष्यों की निगरानी प्रक्रिया में प्रगति मूलरूप से संकेतकों पर निर्भर होती है।
- संकेतक फ्रेमवर्क (प्रारूप) सशक्त होने पर लक्ष्यों के प्रबंधन का उपकरण बनाया जा सकता है जिससे देशों और विश्व समुदाय को विकास नीतियां अपने हिसाब से बनाकर आवश्यक आबंटन निर्धारित करने में आसानी हो जाती है। इनसे स्थायी विकास की दिशा में हुई प्रगति आंकने और स्थायी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सभी हितार्थियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

पंचायतों के लिए डैशबोर्ड

- स्थायी विकास लक्ष्यों को स्थानीय रूप देने के लिए निगरानी तंत्र बनाने के वास्ते निर्णय लेने वालों, नीति बनाने वालों और सेवा प्रदाताओं को इन सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से समय पर सही जानकारी और डेटा की जरूरत होती है।
- डैशबोर्ड से राज्य, जिला और स्थानीय स्तर के अधिकारी लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और स्थानीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति को आंक सकते हैं।
- इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार, उद्योग और ऊर्जा आदि विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर डेटा के नवाचार संसाधनों की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- स्थानीय और राज्य स्तर पर स्थायी लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी में मदद मिलेगी।

स्थायी विकास लक्ष्यों की योजना और उसे मॉनीटर करना

- निगरानी और आकलन प्लेटफॉर्म स्थायी विकास लक्ष्यों और पंचायत विकास योजनाओं तथा अन्य प्रारूपों को ट्रैक, मॉनीटर और रिपोर्ट करने में सहायता करने के लिए विकसित किया जाता है।
- यह यूजर फ्रेंडली और वेब-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो संचार और समन्वयन की खामियों को दूर करता है।

डेटा डैशबोर्ड

- *डेटा डैशबोर्ड जानकारी को इंटरएक्टिव इंट्यूटिव और विजुअल तरीके से प्रदर्शित करते समय मुख्य क्षेत्रों के विभिन्न डेटा-सैटों की पूरी बारीकियों के मॉनीटरिंग, आकलन, विश्लेषण और खोज के केंद्रीयकृत और इंटरएक्टिव तरीके उपलब्ध कराता है।*
- *ऑनलाइन वातावरण में कार्यशील अंतर-दृष्टि विकसित करने में यूजर्स की मदद के लिए ऐतिहासिक डिजाइन, अंतर-संबंध और ट्रेंड्स का पता लगाने के लिए डेटा-सैट चुनकर उन्हें विजुअल-ग्राफिक विधि से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को ही ऑनलाइन डेटा विजुएलाइजेशन कहते हैं।*

- आधुनिकतम संचार-पहल अपनाकर पंचायत विकास योजनाएं बनाने की प्रक्रिया को चुस्त और प्रभावी बनाया जाता है; इसके तहत स्थायी विकास लक्ष्यों और राष्ट्रीय परिणामों का संचार शामिल रहता है और निगरानी और आकलन चरण में इसका अहम प्रभाव पड़ता है क्योंकि इसमें उन्नत संचार चैनल और अधिक पारदर्शिता अपनाई जाती है और क्रियान्वयन पूरी तरह खुले रूप से होता है।
- यह प्लेटफॉर्म वन-स्टॉप-शॉप के रूप में सभी को व्यस्त

रखता है जहां लोग नवीनतम जानकारी और सामग्री पा सकते हैं। व्यापक रूप में यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय और राज्य महत्व का लक्ष्य-वार विश्लेषण हर वर्ष के लिए दर्शाता है। साथ ही ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर भी वर्ष-वार स्थिति देखी जा सकती है।

राष्ट्रीय संकेतकों के लक्ष्य

- स्थायी विकास लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में उपलब्धियों के आधार पर पंचायत के कामकाज की प्रगति का आकलन करना।
- वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति के आधार पर स्वास्थ्य स्पर्धा को बढ़ावा देना।
- ऐसे क्षेत्रों की पहचान में मदद देना। जिन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।
- एक-दूसरे की सफलताओं से सीखने के लिए प्रेरित करना।
- सांख्यिकीय प्रणाली की खामियों को उजागर करना और उन क्षेत्रों का पता लगाना जहां और ज्यादा बार डेटा एकत्र करने की जरूरत है।

भारत को 'खेल राष्ट्र' बनाने का लक्ष्य

- ग्रामीण भारत में विभिन्न प्रकार के अनेक खेल आयोजन देखने को मिलते हैं। खेलों से कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है- लोगों को फिट रखना, सद्भाव बनाए रखना, रचनात्मक क्षेत्रों में युवाओं की ऊर्जा का उपयोग करना, उन्हें मादक पदार्थों के सेवन से दूर रखना और कई अन्य लाभ जिनमें युवा वर्ग को गरीबी की गिरफ्त से बाहर निकालना है।
- भारत सरकार ने हाल के वर्षों में भारत को एक 'खेल राष्ट्र' के रूप में स्थापित करने के लिए कई पहल की हैं जैसे कि खेलो इंडिया, टॉप्स (टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना) आदि जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बल दिया जा रहा है।

भारत में ग्रामीण खेल

- भारत में खेल सदियों से आम जनजीवन का हिस्सा रहे हैं। भारत में उमंगपूर्ण खेल गतिविधियों के मौजूद होने के कई प्रमाण हैं।
- रामायण और महाभारत जैसे हमारे महाकाव्य तीरंदाजी, कुश्ती, घुड़सवारी, रथ दौड़ आदि जैसे खेल प्रतियोगिताओं का उल्लेख हैं। उदाहरण के लिए महाभारत काल में भी कुश्ती एक अत्यधिक लोकप्रिय खेल रहा है।
- आज भारत को कुश्ती में अतर्राष्ट्रीय मंचों (जैसे राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक) में प्राप्त कई उत्कृष्ट उपलब्धियों के कारण इस खेल में एक महाशक्ति के रूप में जाना जाता है।
- कुश्ती जगत की महानतम घटनाक्रमों में से एक महिला कुश्ती की उन्नति और विकास है। इस बदलाव ने महिलाओं के लिए प्रयुक्त 'फेयरर सेक्स' की अवधारणा को समाप्त कर दिया है।
- ग्रामीण भारत की युवतियों और महिलाओं के अपने रोल मॉडल हैं जो उनके जैसे हैं, समान पृष्ठभूमि से आते हैं और सफल होने के लिए चुनौतियों का सामना करते हैं।
- प्राचीनकाल से आज तक कुश्ती युवाओं को रोमांचित करती रही है और आधुनिक खेल जगत में भारत के बेहतर प्रदर्शन के पीछे इनका बड़ा योगदान है।

मल्लखम्ब: अल्ट्रा जिम्नास्टिक्स

- मल्लखम्ब जिम्नास्टिक्स का एक प्राचीन भारतीय संस्करण है जहां एक खिलाड़ी लकड़ी के एक उर्ध्व खम्भे के ऊपर या उसके साथ हवाई योग और जिमनास्टिक मुद्रा का प्रदर्शन करता है।
- यह खेल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में बेहद लोकप्रिय है और इसका प्रदर्शन करने के लिए अत्यधिक सहनशक्ति, अभ्यास और अनुशासन की आवश्यकता होती है।
- मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने 2013 में 'मल्लखम्ब' को 'राज्य' खेल घोषित कर दिया। मुंबई में आयोजित मल्लखम्ब विश्व चैम्पियनशिप 2019 में अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, जापान, सिंगापुर, इटली सहित 15 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कलारीपयट्टू: प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट

- 'कलारीपयट्टू' जिसे केवल 'कलारी' के नाम से भी जाना जाता है, एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट शैली है जिसका वर्णन दक्षिण भारत के संगम काल में मिलता है।
- यह मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण है जिसका उपयोग प्राचीनकाल में योद्धाओं को तैयार करने के लिए किया जाता था। आज यह एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में प्रचलित है और मुख्य रूप से केरल के युवाओं को आकर्षित करता है।
- यह एक गुरु-शिष्य परंपरा का अनुसरण करता है जहां छात्र (शिष्य) प्रशिक्षण केंद्रों (जिन्हें 'कलारी' कहा जाता है) में एक गुरु से प्रशिक्षण लेते हैं।
- केरल सरकार ने 2021 में कलारीपयट्टू अकादमी की स्थापना की है जो इस उद्देश्य के लिए तैयार किए गए एक विशेष पाठ्यक्रम के माध्यम से औपचारिक रूप से कलारी का प्रशिक्षण प्रदान करेगी।

भारत का ग्रामीण ओलंपिक:

- किला रायपुर खेल महोत्सव जो भारत के 'ग्रामीण ओलंपिक' के रूप में जाना जाता है, एक वार्षिक खेल आयोजन है।
- यह खेल उत्सव पेशेवर खेलों के साथ-साथ ग्रामीण खेलों का एक सही अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है जो केवल मनोरंजन के लिए खेले जाते हैं।

- एथलेटिक स्पर्धाओं में शॉट पुट (गोला फेंक), हॉकी, कबड्डी, ट्रैक रेस शामिल हैं। अन्य खेलों में रस्साकशी, घुड़दौड़, घोड़े की कलाबाजी आदि शामिल हैं।
- महोत्सव का उद्देश्य पेशेवर खेलों में नवोदित प्रतिभाओं के लिए एक मंच प्रदान कर इस क्षेत्र में एक खेल संस्कृति का निर्माण करना है।
- महोत्सव क्षेत्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ है- लोकगीत, भांगड़ा, स्थानीय भोजन आदि का आयोजन के दौरान पुरजोर प्रदर्शन होता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का सशक्तीकरण:

- भारत सरकार ने लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना या टॉप्स को 2014 में युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में पदक हासिल करने हेतु एथलीटों को वित्तीय मदद और अन्य सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- योजना के तहत तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी और कुश्ती जैसे खेलों को 'उच्च प्राथमिकता वाली योजनाओं' के रूप में मान्यता दी गई है।
- रियो 2016 ओलंपिक में 'टॉप्स योजना से लाभांवित पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने भारत के लिए क्रमश: रजत और कांस्य पदक जीते टॉप्स योजना के लाभार्थी पैरालिंपियनों ने रियो में दो स्वर्ण पदक सहित चार पदक जीते।
- 'टॉप्स' योजना का प्रभाव 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे अधिक देखा गया था जहां भारत द्वारा जीते गए 70 में से 47 पदक 'टॉप्स' योजना के लाभार्थी एथलीटों द्वारा प्राप्त किए गए थे। पदकों के मामले में टोक्यो ओलंपिक भारत के लिए सबसे बड़ा ओलंपिक रहा है।
- राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास और व्यक्तिगत विकास के माध्यम के रूप में खेलों को मुख्यधारा में लाने के लक्ष्य से 2018 में 'खेलो इंडिया' योजना 12 वर्टिकलों के साथ शुरू की गई।
- खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर पर दो श्रेणियों में प्रतिभा की खोज शुरू की गई है-
  a) खेलों की संभावित प्रतिभा की पहचान और
  b) सिद्ध प्रतिभा की पहचान।
- संभावित और सिद्ध खिलाड़ियों के चुनाव हेतु देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए कई ग्रासरूट जोनल टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी का गठन किया गया है।
- योजना के प्रारंभिक प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने 8750 करोड़ रुपये के अनुमानित बजट के साथ योजना को 2021-22 से 2025-26 तक विस्तारित करने के लिए एक व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ज्ञापन प्रस्तुत किया है।
- जहां केंद्र सरकार ने भारत को एक 'खेल राष्ट्र' में बदलने के लिए सुधार मार्ग अपनाया है वहीं खेल संस्कृति को पोषित करने में राज्यों की भूमिका समान रूप से महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारत को एक 'खेल राष्ट्र' के रूप में परिवर्तित करना:

- भारत सरकार की मौजूदा योजनाओं जैसे- समग्र शिक्षा, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, आदि में देश के सुदूर भागों में खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है।
- भारत में स्कूली शिक्षा की प्रमुख योजना समग्र शिक्षा में ऐसे घटक हैं जो विशेष रूप से स्कूलों को खेल उपकरण प्रदान करने और खेलो इंडिया योजना को बढ़ावा देने पर केंद्रित हैं।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के तहत भारत के प्रत्येक शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉक में कम से कम एक आवासीय बालिका विद्यालय स्थापित किया गया है।
- यह योजना आवासीय पद्धति में कक्षा VI-XII तक उपेक्षित समुदायों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) और अल्पसंख्यकों की लड़कियों को उच्च गुणवत्तायुक्त समग्र शिक्षा प्रदान करती है।
- योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक 'खेल' हैं और इन विद्यालयों में हॉकी, कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि खेलों की सुविधाएं विकसित की गई हैं।
- सरकार का लक्ष्य देश के आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को समग्र शिक्षा प्रदान करना है। इन स्कूलों में खेलों पर खासा ध्यान दिया जाता है।
- खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की योजना बनाई गई है और इसे सभी एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में लागू किया गया है।
- खेल एक वैज्ञानिक शिक्षा शैली है और भावी प्रतिभाओं को विकसित करने और भारत में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक युक्तिपूर्ण रोडमैप की आवश्यकता है।
- 'एक राज्य एक खेल' नाम से एक अभियान शुरू करना उपयोगी हो सकता है जिसमें प्रत्येक राज्य सरकार एक प्रमुख खेल की पहचान करेगी जिसमें उसे अन्य खेलों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल हो जबकि अन्य खेलों को थोड़ी कम प्राथमिकता दी जा सकती है।

निष्कर्ष

- खेल की परंपरा कुछ सहस्राब्दियों पूर्व की भारतीय संस्कृति में गहरी जड़ जमाए हुए है।
- हाल ही में भारत सरकार ने टॉप्स, खेलो इंडिया, फिट इंडिया आदि जैसी कई पहल की हैं जिनमें भारत के खेल परिदृश्य को बदलने की क्षमता है।

- ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व चैंपियनशिप में हाल की सफलताएं बेहद उत्साहजनक रही हैं। देश में खेल को आजीविका के रूप में देखने वाले अभिभावकों और युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
- भारत में अभी हम एक जीवंत खेल संस्कृति के संक्रमण बिंदु पर हैं जो भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन और पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के कारण तेजी से विकसित होगी।

भारत में खेलों को प्रोत्साहन

- खेल गतिविधियों का व्यक्ति के बेहतर स्वास्थ्य एवं जीवन में अमूल्य योगदान होता है। खेल गतिविधियां व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
- खेल गतिविधियां बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य व मनोरंजन के साथ-साथ व्यक्तियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को भी विकसित करती हैं।
- खेल किसी भी राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक विकास के एक महत्त्वपूर्ण घटक एवं परिचायक के रूप में उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।
- खेल गतिविधियां न केवल व्यक्तियों, युवाओं एवं समुदायों के बीच स्वस्थ जीवनशैली के विकास में बल्कि कई दृष्टिकोणों से व्यक्ति, समाज और देश के विकास में मददगार होती हैं। जिनमें प्रमुख है-
  - सकारात्मक सोच एवं रचनात्मकता विकसित करने में सहायक;
  - टीम भावना, रणनीतिक एवं विश्लेषणात्मक सोच का विकास;
  - लक्ष्य निर्धारण, जोखिम लेने एवं नेतृत्व कौशल का विकास;
  - बेहतर समय प्रबंधन, लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तीकरण;
  - समावेशी समाज के निर्माण में सहायक;
  - ग्रामीण पर्यटन एवं अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान;
  - युवाओं व खिलाड़ियों के बेहतर भविष्य के अवसर सृजन में सहायक खेल शिक्षा व शोध कार्य से आजीविका के अवसर के रूप में;
  - खेल वस्तुओं के उत्पादन, निर्यात एवं व्यापार के क्षेत्र में रोजगार सृजन में सहायक इत्यादि।
- खेल गतिविधियां एक स्वस्थ समाज के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक सम्पन्नता को सभी के साथ साझा करने में बहुमूल्य योगदान देती हैं।
- विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले विकासशील भारत में खेलों व खिलाड़ियों को विकसित तथा पोषित करने की जिम्मेदारी सरकारों की रही है।
- यहाँ खेलों व खिलाड़ियों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने की दिशा में निजी क्षेत्र की भूमिका सीमित रही है।
- भारत में विभिन्न खेलों व खिलाड़ियों को समाधित करने के साथ-साथ खेलों के संपूर्ण प्रबंधन को निम्नलिखित दो पहलुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-
  1. नीतिगत पहल
  2. संस्थागत पहल
- राष्ट्रीय स्तर पर भारत में खेलों को संगठित व व्यवस्थित ढांचागत स्वरूप के माध्यम से विकसित व प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय खेल नीति 1984 पहली महत्वपूर्ण पहल थी।
- वर्ष 2001 में राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 2014 में राष्ट्रीय युवा नीति के अंतर्गत भारत में विभिन्न खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में नीतिगत प्रयास किए गए।
- राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में व्यक्तियों, विशेषकर युवाओं को खेलों से जोड़ने की दिशा में विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन व खेलों के प्रबंधन में सुशासन को विभिन्न नीतिगत पहलों, कार्यक्रमों व योजनाओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

भारत में खेलों के प्रबंधन हेतु संस्थागत पहल

- भारत में विभिन्न खेलों व खिलाड़ियों के संपूर्ण प्रबंधन हेतु भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संस्थागत पहल की जाती रही है।
- युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार देशभर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ खेलों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अग्रसर एवं कार्यरत है।

भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI)

- विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता हेतु विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज और उनके पोषण के उद्देश्य से भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) की विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जाती हैं।

भारत में खेलों के प्रोत्साहन हेतु प्रमुख योजनाएं

- युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ-साथ खेलों में उत्कृष्टता हेतु विभिन्न योजनाओं का संचालन किया

जा रहा है:

(i) खेलो इंडिया योजना;

(ii) राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता;

(iii) अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार;

(iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन;

(v) पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष;

(vi) राष्ट्रीय खेल विकास कोष; और

(vii) भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से चलाए जा रहे खेल प्रशिक्षण केंद्र।

'खेलो इंडिया' योजना

- खेल मंत्रालय, भारत सरकार की 'खेलो इंडिया' योजना एवं 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' (ईबीएसबी) कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीण व स्वदेशी/आदिवासी खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- भारत को एक महान खेल राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भारत में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 'खेलो इंडिया' कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।
- साथ ही, भारत सरकार का खेल मंत्रालय खेलों को शहरी के साथ-साथ ग्रामीण, आदिवासी तथा पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रोत्साहित करने की दिशा में कार्यरत है।
- 'खेलो इंडिया' योजना की 'स्पोर्ट्स फॉर वीमेन' योजना के अंतर्गत, विशेष रूप से महिलाओं को विभिन्न खेलों हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- खेलो इंडिया योजना की "राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य खेल अकादमियों को समर्थन" वर्टिकल के तहत, 'खेलो इंडिया' खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए खेल अकादमियों को मान्यता दी जाती है।
- देशभर में अब तक ऐसी 236 खेल अकादमियों को मान्यता मिल चुकी है।
- खेलो इंडिया योजना के 'राज्य-स्तरीय खेलो इंडिया केंद्र' वर्टिकल के तहत इस मंत्रालय ने देश भर में/1,000 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है, जिनमें से 360 खेलो इंडिया केंद्र पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं।

नेहरू युवा केंद्र संगठन

- ग्रामीण युवाओं में खेल संस्कृति को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ ब्लॉक एवं जिला स्तर पर युवा क्लबों को खेल के विभिन्न सामान/उपकरण उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अंतर युवा क्लब खेल प्रतियोगिता के आयोजन के माध्यम से युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाता है।

अन्य महत्त्वपूर्ण योजनाएं

- भारत सरकार ने ओलंपिक और एशियाई खेलों जैसे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए कई कदम उठाए हैं:
  - 24 'खेलो इंडिया' राज्य उत्कृष्टता केंद्रों की देशभर में शुरुआत;
  - राष्ट्रीय खेल महासंघ हेतु सहायता की योजना;
  - अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों हेतु खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं प्रतिस्पर्धात्मक अवसर प्रदान करना;
  - टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत ओलंपिक खेलों एवं एशियाई खेलों सहित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पदक जीतने की संभावना वाले खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना;
  - पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कोष के तहत कठिन परिस्थितियों में रहने वाले खिलाड़ियों को एवं मृत खिलाड़ियों के परिवारों को पांच लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान करना, इत्यादि।
- युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खेल विज्ञान और अनुसंधान केंद्र (एनसीएसएसआर) की योजना का उद्देश्य उत्कृष्ट एथलीटों के श्रेष्ठ प्रदर्शन के संबंध में उच्चस्तरीय अनुसंधान, शिक्षा और नवाचार को समर्थन प्रदान करना है।
- एनसीएसएसआर योजना के प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:
  - खेल प्रदर्शन को बढ़ावा देने, भरण-पोषण और वृद्धि हेतु वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग;
  - एथलीटों की अधिकतम क्षमता को विकसित करना;
  - खेल विज्ञान के बारे में जानकारियों का प्रसार करना;
  - अनुपूरक/स्वदेशी खाद्य तैयारियों का परीक्षण और प्रमाणीकरण;
  - खेल प्रदर्शन में आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक दवाओं का प्रयोग;
  - खेल में चोटिल खिलाड़ियों का प्रबंधन और पुनर्वास;
  - खेल विज्ञान और खेल चिकित्सा में आधारभूत और व्यावहारिक अनुसंधान।

खेलों के प्रोत्साहन में राज्यों की भूमिका

- भारतीय संविधान की सातवीं सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 33 के अंतर्गत 'खेल' राज्य का विषय हैं। खेलों के प्रोत्साहन एवं विकसित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है।

- विभिन्न खेलों के प्रोत्साहन एवं विकसित करने तथा राज्यों में खेल का बुनियादी ढांचा व खेल सुविधाएं सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं हेतु तैयार करने की दिशा में केंद्र सरकार सहायता प्रदान करती है।
- राज्यों में खेल शिक्षा एवं शोध कार्यों को प्रोत्साहन देने हेतु खेल विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है; राज्य सरकारों द्वारा खेलों के प्रोत्साहन में अनेक महत्व पूर्ण पहल की जा रही है।
  - ओडिशा सरकार, भारतीय हॉकी टीम को आगामी एक दशक तक प्रायोजित करेगी।
  - उत्तर प्रदेश सरकार ने 2032 में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों तक भारतीय कुश्ती टीम को गोद लिया है।
  - मिजोरम में हाल ही में खेलों को 'उद्योग' का दर्जा दिया गया है। इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य राज्य में खेलों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन देना है ताकि निजी कंपनियों को खेलों में निवेश हेतु आकर्षित किया जा सके।

खेलों में उपलब्धियां

- भारत में केंद्र व राज्य सरकारों की विभिन्न नीतिगत एवं संस्थागत पहलों तथा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रयासों को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में पदक के माध्यम से समझा जा सकता है।
- टोक्यो ओलम्पिक 2020 में भारत कुल 7 पदक जीतकर 48वें स्थान पर रहा और टोक्यो पैरालम्पिक 2020 खेलों में कुल 19 पदक लेकर 24वें स्थान पर रहा।
- 2018 में गोल्ड कोस्ट 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत कुल 66 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा था और 2018 में ही हुए एशियन गेम्स में 69 पदकों के साथ 8वें स्थान पर रहा।

खेलों में प्रमुख चुनौतियां

- मानव जीवन में विभिन्न खेलों एवं खेल गतिविधियों की उपयोगिता, चाहे वह बेहतर स्वास्थ्य से जोड़कर, या बेहतर भविष्य के तौर पर, या बेहतर जीविकोपार्जन के रूप में हो, को प्राय: उतनी मान्यता नहीं दी गई है।
- फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 62 प्रतिशत युवा विभिन्न खेलों में रूचि तो रखते हैं।
- आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारों द्वारा चलाई जा रही खेल प्रोत्साहन की योजनाओं की संपूर्ण जानकारी का अभाव विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से पता लगाया जा सकता है।

खेल में युवाओं हेतु रोजगार के अवसर

- ग्रामीण एवं शहरी युवाओं को, खेल गतिविधियों में भाग लेने के अलावा निम्नलिखित खेल संबंधी विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार, स्वरोजगार एवं उद्यमिता हेतु नए अवसरों का सृजन किया जा सकता है।
- इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन के अनुसार, खेल उद्योग श्रम-आधारित होने के कारण, पांच लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं।

ग्रामीण भारत में खेल प्रोत्साहन हेतु सुझाव

- खेलों के प्रति जन सामान्य की सोच "खेलोगे, कूदोगे, बनोगे लाजवाब", विकसित करने में व्यवहारात्मक परिवर्तन पर विशेष जोर;
- ग्रामीण-स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ना, जिससे वे अपनी प्रतिभा विकसित कर अपने राज्य व राष्ट्र हेतु विभिन्न खेलों में पदक विजेता बन सकें;
- ग्रामीण एवं ब्लॉक स्तर पर स्थानीय खेलों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष खेल-त्यौहार के रूप में वातावरण तैयार कर विभिन्न खेल प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा सकता है;
- ग्राम पंचायत की विकास योजनाओं के माध्यम से खेल वस्तुओं की खरीदारी, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल अधोसंरचना का निर्माण एवं खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता जैसे कार्यों के माध्यम से विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन के साथ-साथ इन कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित करना;
- निजी क्षेत्र के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों, जनप्रतिनिधियों, प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा खेल या खिलाड़ियों को गोद लेने की संस्कृति को विकसित करने की पहल पर जोर देकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में विभिन्न खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा सकता है;
- सामाजिक नवाचार के माध्यम से विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना। जैसा कि हरियाणा सरकार ने राज्य में खेलों को बढ़ावा देने हेतु युवा माताओं के सहयोग से उनके बच्चों को हर प्रकार की खेल गतिविधियों से जोड़ने हेतु मदर्स फॉर स्पोर्टस एंड फिटनेस एप के माध्यम से प्रयास किया है।

- खेल गतिविधियां एक स्वस्थ समाज के निर्माण में अमूल्य योगदान देने के साथ-साथ जनचेतना, सामाजिक समरसता एवं आर्थिक-सांस्कृतिक विकास को भी उत्प्रेरित करती हैं। समाज में खेलों को शिक्षा के समतुल्य माने जाने वाली सोच को जनसामान्य में विकसित करने की ओर प्रयास करना चाहिए, तभी एक बेहतर समावेशी एवं विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों का विकास

- कोरोना संकट के बीच टोक्यो में हुए ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की ऐतिहासिक सर्वश्रेष्ठ सफलता को देखते हुए अब हर कोई पूरे विश्वास के साथ यह कहने लगा है कि भारत में 'खेल संस्कृति' विकसित हो रही है।
- विश्व-स्तर पर खेलों में भारत के विकास का केंद्रबिंदु दूरदराज क्षेत्रों के बेहद पिछड़े हुए वे गांव हैं जहां अभी तक खेलों की मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं हैं। अनेक राज्य सरकारें ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के गांव या उसके आसपास के क्षेत्रों में स्टेडियम या ट्रेनिंग सेंटर बनाने की घोषणाएं कर रही हैं या योजनाएं बना रही हैं।
- 'खेल' वैसे तो राज्य का विषय हैं लेकिन केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों को साथ लेकर देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने में जुटी हुई है।
- 'न्यू इंडिया' भारत की कुछ अलग तस्वीर दिखाता है। प्रधानमंत्री के अनुसार हमारे गांव और दूरदराज के इलाके प्रतिभा से भरे हुए हैं, हमें अपने युवाओं के बारे में सोचना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें सभी संसाधन एवं सुविधाएं मिलें।
- इन क्षेत्रों में कई युवा खिलाड़ी हैं जिनमें पदक जीतने की क्षमता है। आज देश उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
- स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान करने के लिए देश भर में 360 खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। जल्द ही यह संख्या बढ़ाकर 1,000 कर दी जाएगी।
- खिलाड़ियों को उपकरण, मैदान और अन्य संसाधन तथा बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जा रहा है। देश खुले दिल से अपने खिलाड़ियों की मदद कर रहा है।
- खेलों को अगले स्तर तक ले जाने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को लेकर ओलंपिक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इनके द्वारा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन में सधार के लिए रोडमैप बनाया गया है।
- टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया योजना के जरिए केंद्र सरकार निचले से उच्च स्तर तक, गांवों से शहरों तक खेलों के विकास के लिए कार्य करती है। हमारे खिलाड़ी इन दो बड़ी योजनाओं का हिस्सा बनने के लिए पुरजोर प्रयास करते दिखाई देते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी तैयार करने के लिए अच्छे कोच, अच्छी खुराक व आधुनिक सुविधाओं वाला ट्रेनिंग सेंटर जरूरी है, लेकिन इसके साथ-साथ यातायात के सरकारी व प्राइवेट साधनों का होना भी बहुत जरूरी है।
- अच्छी सड़कें भी खिलाड़ियों को तैयार करने में मददगार होती हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में जहां अच्छी सड़कें नहीं हैं वहां यात्रा कितनी कष्टदायी होती है, इस तथ्य को वहां के निवासियों से बेहतर कोई और नहीं जान सकता है।
- उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के दूरदराज के इलाकों में ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने के साथ-साथ बेहतरीन हाइवे और गांव-गांव को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है।
- भारत में खेल संस्कृति को विकसित करने के लिए अपने तरीकों और प्रणाली में सुधार करते रहना होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देने के साथ-साथ पारंपरिक खेलों को भी नई पहचान मिल रही है।
- 2018 में पहली बार आयोजित 'खेलो इंडिया' गेम्स भारत में जमीनी स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के लिए एक प्रमुख बदलाव लाए हैं। कई बार खेलो इंडिया गेम्स का आयोजन किया गया है जिसमें यूथ, यूनिवर्सिटी और विंटर गेम्स शामिल हैं।
- खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ ब्लॉक एवं जिला-स्तर पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शैक्षणिक संस्थानों में नवोदित प्रतिभाओं की शीघ्र पहचान करने पर भी सरकार का जोर है।
- खेलमंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से राष्ट्र के खेल इकोसिस्टम को मजबूत करने के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए केआईएससीई, केआईसी के साथ-साथ अकादमियां खोलने के प्रस्ताव भेजने का भी आग्रह किया है जिससे ग्रामीण भारत में खेलों का विकास तेजी से हो सकेगा। एक ऐसा डैशबोर्ड बनाने पर भी विचार किया जा रहा है जहां हर राज्य, जिला और ब्लॉक में उपलब्ध खेल के बुनियादी ढांचे से संबंधित डेटा उपलब्ध होगा।
- यह डैशबोर्ड कोचों की उपलब्धता, इनडोर स्टेडियमों में किस तरह के खेल खेले जाएंगे या आउटडोर खेलों आदि के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारियां देगा और ये सभी विवरण एक बटन दबाने पर उपलब्ध होंगे।
- विभिन्न खेलों के लिए 'प्रतिभा खोज' कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिससे देश में कम उम्र में ही प्रतिभाओं की पहचान की जा सके और उन्हें भविष्य की प्रतियोगिताओं के लिए अच्छी तरह प्रशिक्षित कर सकें।
- राज्यों से अनुरोध किया गया है कि खिलाड़ियों को प्रतिस्पर्धा के अधिक से अधिक अवसर देने के लिए और प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं और उन्हें राज्य-स्तर, जिला-स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर अधिक स्पर्धाओं में भाग लेने का मौका मिले।

- खेल मंत्रालय ने ग्रामीण, आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश भर में खेलों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित योजनाएं तैयार की हैं-
  1. खेलो इंडिया योजना
  2. राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता
  3. अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों को विशेष पुरस्कार
  4. राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पेंशन
  5. पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष
  6. राष्ट्रीय खेल विकास कोष और
  7. भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन।
- इन योजनाओं से लाभान्वित होने वाले ज्यादातर खिलाड़ी देश के ग्रामीण, पिछड़े, आदिवासी और महिला आबादी से आते हैं तथा उन्हें योजनाओं के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार आवासीय एवं गैर-आवासीय आधार पर नियमित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रतिभा की पहचान करने के लिए भारत को उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पूर्व इन पांच क्षेत्रों में बांटा गया है।
- विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में जिला स्तर पर योजना के तहत अधिसूचित प्रत्येक खेलो इंडिया केंद्र प्रति खेल पांच लाख रुपये का एक बार मिलने वाला अनुदान और प्रति खेल पांच लाख रुपये का आवर्ती अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र है।
- राष्ट्रीय खेल संघों को सहायता देने से जुड़ी योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
- टॉप्स के तहत, ओलंपिक 2028 सहित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए संभावित पदक विजेताओं को खास प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- देश का हर युवा खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने की चाह लिए अभ्यास करता है, उसका शुरुआती लक्ष्य 'खेलो इंडिया' और उसके बाद 'टॉप्स' योजना में शामिल होने का रहता है। इससे उसके देश-विदेश में प्रशिक्षण, नवीनतम उपकरण और अन्य हर संभव सहायता के साथ आर्थिक मदद भी खूब हो जाती है।
- भारतीय खेल प्राधिकरण (साई), युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करने व उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने को लेकर प्रशिक्षित करने के लिए देशभर में निम्नलिखित खेल प्रोत्साहन योजनाओं को लागू कर रहा है।

राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता (एनएसटीसी)

- टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (टॉप्स) के तहत भारत सरकार ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की तैयारी कर रहे भारत के शीर्ष खिलाड़ियों को सहायता प्रदान करती है।
- मंत्रालय की सामान्य योजनाओं के तहत अन्य सहायता उपलब्ध नहीं होने पर चयनित खिलाड़ियों को अनुकूलित प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय खेल विकास कोष (एनएसडीएफ) से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- कोर ग्रुप खिलाड़ियों को आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस 50,000 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है। ओपीए के अलावा, खिलाडी द्वारा पेश प्रशिक्षण योजना के पूरे खर्च को टॉप्स के तहत प्रदान किया जाता है।
- मिशन ओलंपिक सेल (एमओसी) इस खर्च पर विचार और इसका अनुमोदन करती है। वर्तमान में, इस योजना के तहत कोर ग्रुप के रूप में 147 व्यक्तिगत खिलाड़ियों और 2 हॉकी टीमों (पुरुष और महिला) का चयन किया गया है।
- टॉप्स विकास समूह के खिलाड़ी को 25,000 रुपये का ओपीए और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (एनसीओई) में अनुकूलित प्रशिक्षण सहायता मिल रही है। वर्ष 2021 में खेल मंत्रालय ने 14.30 करोड़ रुपये के कुल बजट अनुमान के साथ 7 राज्यों में कुल 143 'खेलो इंडिया' केंद्र समर्पित किए।
- खेल मंत्रालय द्वारा देश भर में जमीनी स्तर के खेल बुनियादी ढांचे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में खेलो इंडिया केंद्र शुरू किए गए हैं।
- खेल मंत्रालय ने जून 2020 में देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक खेलो इंडिया केंद्र के हिसाब से 4 साल की अवधि में 1,000 नए खेलो इंडिया केंद्र खोलने की योजना बनाई थी। जबकि इससे पहले कई राज्यों में 217 खेलो इंडिया केंद्र खोले गए थे।
- उत्तर-पूर्वी राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख के जिलों के लिए अपवाद के रूप में प्रत्येक जिले में दो खेलो इंडिया केंद्र होंगे। इसमें सरकार काफी हद तक सफल भी रही है और इनसे ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं में बढ़ोत्तरी होनी शुरू हो गई है।
- खिलाड़ियों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय कल्याण कारी निधि योजना के तहत वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे भी ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों के विकास में मदद मिलती है। यह योजना निम्नलिखित उद्देश्य के लिए है-
  1. गरीबी की हालत में रहने वाले खिलाड़ियों की सहायता;
  2. मृतक खिलाड़ियों के परिवारों की सहायता,

खिलाड़ियों या परिवार के सदस्यों को इलाज के लिए मदद;

3. खेल प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण और खेल के दौरान लगी चोटों के लिए सहायता;
4. प्रशिक्षण, उपकरणों की खरीद और राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी के लिए सहायता;
5. कोच और सहायक कर्मियों को सहायता;
6. कोच और सहायक कर्मियों को इलाज के लिए मदद।

- जब गांव-गांव तक फिटनेस की जागरूकता फैलेगी तो निश्चित रूप से देश को अधिक बेहतर, स्वस्थ और तंदुरुस्त खिलाड़ी मिल सकेंगे जो अपने दमखम, चपलता और मानसिक मजबूती के साथ खेल कौशल से विपक्षी खिलाड़ियों के छक्के छुड़ा सकेंगे।
- केंद्र सरकार खेलों के बुनियादी ढांचे को विकसित देशों में उपलब्ध बुनियादी ढांचे के अनुरूप बनाने के लिए व्यापक योजना के तहत कार्य कर रही है।
- जिसका लक्ष्य दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों को ज्यादा-से-ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि वे ओलंपिक खेलों में अधिक से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर सकें।

भारत में खेलों में तकनीकी क्रांति

- खेल को कुछ इस तरह से पारिभाषित किया जा सकता है- ऐसी तमाम शारीरिक गतिविधियां जो मूल रूप से प्रतिस्पर्धी होती हैं, जिनमें संगठित और आकस्मिक रूप से भागीदारी की जाती है और जो दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करती हैं।
- खेल कई तरीके से लोगों को जोड़ता है। खेल लिंग, वर्ग और संस्कृति की पहचान को तोड़कर समुदायों के बीच एकता की भावना विकसित करते हैं।
- इसके अलावा, यह हौसला बढ़ाने और तनाव घटाने में भी मददगार हैं।
- भारत दुनिया के उभरते हुए देशों में शामिल है और यहां खेल से जुड़े कई कारोबारी अवसर मौजूद हैं। क्रिकेट और हॉकी में भारत के लोगों की काफी दिलचस्पी है, जबकि कुछ गांवों और शहरों में अभी भी पारंपरिक खेलों का प्रचलन जारी है। ऐसे कई पारंपरिक खेलों के आधार पर ही कई आधुनिक खेल विकसित हुए हैं।
- जीवनशैली में अनियमितता की वजह से होने वाली बीमारियों, मसलन मोटापा, मधुमेह, लकवा आदि में बढ़ोत्तरी की वजह से 'खेल' और 'फिटनेस' को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।
- 'बिजनेस वायर' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021-2026 के दौरान भारतीय खेल और फिटनेस सामानों का बाजार 8.6 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़ सकता है।
- खेलों की दुनिया का संबंध पहले सिर्फ मनोरंजन से था और अब इसका दायरा काफी व्यापक हो गया है, जिसमें अलग-अलग पक्ष शामिल हैं।
- अत्याधुनिक तकनीक के आगमन के साथ ही खेल उद्योग में भी बदलाव हो रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी रुझानों और प्रदर्शन पर नजर रखने और उनके बारे में समझने में है।
- खिलाडी के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए खेल में तकनीक का सहारा लिया जाता है। इसे 'खेल तकनीक' के तौर पर जाना जाता है।
- खेल तकनीक में कई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, रोबोटिक्स, ड्रोन, डिजिटाइजेशन आदि। इन तकनीकों के जरिए खेलों की स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिली है।
- खेलों की दुनिया से जुड़े हर चरण में तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है, मसलन खेलों के प्रसारण, दर्शकों जोड़ने, आधुनिक उपकरण, लाइव प्रदर्शन आदि। साथ ही, खिलाड़ी के अभ्यास में भी तकनीक अहम भूमिका निभा सकती है।
- डिजिटल तकनीक आने वाले समय में खेलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस तकनीक के जरिए पारंपरिक खेलों में खिलाड़ी और टीम के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सकता है।
- साथ ही, दर्शकों के अनुभव को बेहतर बनाने और नए दर्शकों का ध्यान खींचने में भी यह उपयोगी साबित हो सकती है।
- धीमी गति में रि-प्ले, डेटाबेस स्टोरेज और दूसरे खिलाड़ियों से तुलना आदि में तकनीक के इस्तेमाल से खिलाड़ियों को बड़े पैमाने पर अपना खेल सुधारने में मदद मिली है।
- तकनीक के माध्यम से खिलाड़ी किसी खास अवधि में रफ्तार, दिशा, स्विंग, उछाल आदि की बेहतर तरीके से निगरानी कर पाते हैं।
- खिलाड़ी और टीम के प्रदर्शन के लिए जीव विज्ञान और तकनीक (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स) का सहारा लिया जा सकता है।

- इस तरह, तय समय में खिलाड़ियों के प्रदर्शन, शारीरिक गतिवधि, रफ्तार, दिल की धड़कन, शरीर के तापमान आदि की रियल टाइम जानकारी हासिल की जा सकती है। इस तरह की जानकारी का इस्तेमाल खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर करने, चोट को रोकने, खिलाड़ियों की सुरक्षा को बेहतर बनाने और खेल की रणनीति तैयार करने में किया जा सकता है।
- प्रतिद्वंदी टीमें दूसरी टीम के खिलाफ रणनीति बनाने में भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। खिलाड़ियों के कपड़े, खेल उपकरणों आदि में सेंसर का इस्तेमाल कर रियल-टाइम डेटा इकट्ठा किया जा सकता है।
- अभ्यास सत्र के दौरान, खिलाड़ी 'वर्चुअल रियलटी' और 'ऑगमेंटेड रियलिटी' जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर मैच जैसे माहौल में बेहतर ढंग से अभ्यास कर सकते हैं। इससे जगह की कमी और प्रतिकूल मौसम जैसी दिक्कतों के बावजूद मैच का अभ्यास करना मुमकिन होता है।
- ये तकनीक रेफरी के लिए भी मददगार होंगी और वे खेल को ज्यादा बारीकी से देख सकेंगे। साथ ही, उनके पास रियल-टाइम डेटा का एक्सेस भी होगा। इन सुविधाओं की मदद से उसको सही और सटीक फैसले लेने में मदद मिलेगी।
  - 2016 में खिलाड़ियों की जर्सी पर सेंसर लगाए गए, ताकि उनकी सेहत पर नजर रखी जा सके और चोट की रोकथाम में भी मदद मिले।
  - 2017 में बैट पर स्मार्ट चिप लगाई गई, ताकि रफ्तार और एंगल के लिए बेहतर ढंग से विश्लेषण पेश किया जा सके।
  - 2018 के फीफा विश्व में एनएफसी (नियर फील्ड्स कम्युनिकेशन) चिप से लैस 'टेलीस्टार 18 सॉकर बॉल' को पेश किया गया।
- वैश्विक स्तर पर हासिल की गई ये उपलब्धियां निश्चित तौर पर प्रशंसा के योग्य हैं। साथ ही, टेक्नोलॉजी के इस दौर में भारत भी पीछे नहीं है, जहां खेल और खेल प्रबंधन के क्षेत्र में डिजिटल मैपिंग, डेटा एनालिटिक्स, मशीन इंटेलिजेंस और अन्य तकनीक की पहुंच मुमकिन हुई है।
- सरकार न सिर्फ इस निवेश को बेहतर खिलाड़ी तैयार करने का जरिया मानती है, बल्कि अर्थव्यवस्था में खेल तकनीक से जुड़े उद्योग के योगदान के महत्व को भी समझती है।
- सरकार इस बाजार में निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को निवेश के लिए भी प्रोत्साहित करने को लेकर बेहद सक्रिय है। टेक महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल जैसी बड़ी कंपनियां भी खेल के क्षेत्र में तकनीकी समाधान पेश कर रही हैं।
- खिलाड़ियों के फिटनेस और खेल संबंधी गतिविधियों की निगरानी से लेकर दर्शकों को जोड़ने संबंधी तकनीक शामिल हैं। इस क्षेत्र की बड़ी कंपनियां और स्टार्टअप भी मैंचेस्टर यूनाइटेड, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और टेनिस प्रोफेशनल संघ जैसी इकाइयों के साथ साझेदारी कर रही हैं।
- भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने 2019 में ब्रिटिश टेक्नोलॉजी कंपनी 'स्टैटस्पोर्ट' के साथ समझौता किया। बोर्ड ने जीपीएस आधारित निगरानी और विश्लेषण के लिए कंपनी के साथ यह समझौता किया है। इसके तहत, खिलाड़ियों की सक्रियता की निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
- खेल तकनीक के क्षेत्र में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देकर नई संभावनाओं के लिए बेहतर गुंजाइश बनाई जा सकती है।
- 'स्टांसबीम' खिलाड़ियों के प्रशिक्षण की रियल-टाइम निगरानी की सुविधा मुहैया कराती है। साथ ही, कोच कहीं से भी खिलाड़ियों को सझाव दे सकते हैं।
- 'स्टांसबीम' का प्लेटफॉर्म रिकॉर्ड किया गए प्रशिक्षण वीडियो, अभ्यास के सत्र, स्विंग मेट्रिक आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराता है।
- कोच को भी इन चीजों की उपलब्धता मुहैया कराई जाती है और वे रियलटाइम में सुझाव दे सकते हैं। प्रशिक्षण का यह वर्चुअल प्लेटफॉर्म इस महामारी के दौरान क्रिकेट कोचिंग को डिजिटाइज कर इसे पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। भारत में खेलों में तकनीकी क्रांति की शुरुआत हो चुकी है।
- हालांकि, यहां खेल तकनीक अभी बेहद शुरुआती दौर में है, लेकिन लगातार बेहतर नतीजे देखने को मिल रहे हैं। इससे निवेशकों का भरोसा भी बढ़ा है।
- यदि भारत को खेल के क्षेत्र में महाशक्ति बनना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा जैसी नई तकनीक का इस्तेमाल करना होगा।
- रिसर्च कंपनी मार्केट सैंडमार्केट्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 में खेल तकनीक का वैश्विक बाजार 17.9 अरब डॉलर है और इसके 2025 तक 17.5 प्रतिशत सीएजीआर की दर से बढ़कर 40.2 अरब डॉलर हो जाने की संभावना है।
- हाल के वर्षों में खेलों से जुड़ी पेशेवर संस्थाओं ने अपनी टीम के प्रदर्शन को बढ़ाने, दर्शकों को जोड़ने, बेहतर आधारभूत संरचना मुहैया कराने और खेल के पूरे अनुभव को एक अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए नई-नई तकनीक को अपनाया है।
- ऐसी तकनीक में डेटा एनालिटिक्स, स्मार्ट स्टेडियम, डिजिटल साइनेज आदि शामिल हैं।

- आज के दौर में खेल, उसके नियम और खिलाड़ियों को बेहतर बनाने में तकनीक की अहम भूमिका है।
- अमेरिका, चीन और ब्रिटेन ने खेलों के लिए डेटा इकट्ठा करने और उसके विश्लेषण आदि के लिए उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर सफलता हासिल की है और भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
- खेल तकनीक में निवेश के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के मकसद से सरकार कुछ और उपायों पर विचार कर सकती है।
- इससे न सिर्फ भारत में खेलों का स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी, बल्कि खेल उद्योग और तकनीक के जरिए खेलों के प्रशिक्षण में भी क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकेगा।

ग्रामीण महिलाओं की खेलों में बढ़ती भागीदारी

- भारत एक ऐसा देश है जहां प्राचीनकाल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर दर्जा प्राप्त था। वह विभिन्न विधाओं, जिन्हें अब खेलों के रूप में खेला जाता है, उनको प्राप्त करती थीं और उनमें पारंगता हासिल करती थीं।
- ब्रिटिश राज में महिलाओं की खेलों में भागीदारी थोड़ी-बहुत बढ़ी लेकिन बेहतर अवसर महिलाओं को आजादी के बाद ही प्राप्त हुए। स्वतंत्रता के पश्चात् महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए बहुत-सी योजनाओं का शिलान्यास हुआ।
- बहुत-सी महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाया।
- ग्रामीण परिवेश की महिलाएं जैसे कि पी.टी. उषा, मीराबाई चानू, मैरी कॉम, गीता फोगाट, दीपिका कुमारी इत्यादि खेल जगत का अभिन्न हिस्सा बनीं जिन्होंने परिस्थितियों के विपरीत जाकर सफलता प्राप्त की और लाखों ग्रामीण महिलाओं को प्रेरित किया।

ओलंपिक और पैरालम्पिक में भारतीय महिलाएं

- ओलंपिक और पैरालम्पिक खेलों में भारतीय महिलाओं ने बेहतरीन प्रदर्शन कर कुल 6 पदक अर्जित किए। पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, अवनी लेखरा, भाविना पटेल ने अपने हुनर के दम पर सिद्ध कर दिया कि इस नए भारत में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहीं हैं।
  - पीवी सिंधु ने ओलंपिक में बैडमिंटन में महिला सिंगल्स में कांस्य पदक जीता।
  - मीराबाई चानू ने ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता।
  - अवनी लेखरा ने पैरालम्पिक राइफल शूटिंग में दो पदक जीतने वाली (स्वर्ण एवं कांस्य) पहली महिला खिलाड़ी बन इतिहास रचा।
  - पैरालम्पिक महिला टेबल टेनिस में भी भारत को पहली बार रजत पदक जीतने का गौरव हासिल हुआ।
  - भाविना पटेल ने भारत की झोली में यह पदक डाला।
- सरकारी योजनाएं खिलाड़ियों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सरकार के द्वारा ढेर सारी सरकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
- इन योजनाओं के द्वारा खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और बेहतरीन कोच भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

पंचवर्षीय योजनाएं

- देश की आजादी के बाद से ही क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं में खेलों और शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया गया।
  - दूसरी पंचवर्षीय योजना के फलस्वरूप नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स की स्थापना हुई। स्टेडियम, स्विमिंग पूल और ओपन एयर थिएटर के निर्माण की शुरुआत हुई।
  - तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय कोचिंग योजना का आरंभ हुआ।
  - शारीरिक शिक्षा, खेल और खेलों के लिए आवंटन चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बढ़ाए गए। कोचिंग सुविधाओं में सुधार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ।
  - छठी पंचवर्षीय योजना में युवा प्रतिभाओं को दी जा रही सुविधाओं पर जोर दिया गया।
  - साहसिक खेलों को सातवीं योजना के दौरान प्रोत्साहन मिला। 1984 में खेल का एक अलग विभाग बना दिया गया।
  - 8वीं योजना से गांवों में खेलों को बढ़ावा मिला। कई ग्रामीण स्कूलों में खेल के मैदानों को विकसित किया गया। बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में खेलों में आधुनिक और वैज्ञानिक सुविधाओं पर जोर दिया गया।

ओलंपिक पोडियम स्कीम (2014)

- ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए हमारे खेल मंत्रालय ने सितंबर, 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम शुरू की।

- इस योजना के तहत खिलाड़ियों को टॉप कोच से कोचिंग और खेल से जुड़े इक्विपमेंट खरीदने में मदद की जाती है।
- खिलाड़ियों को सपोर्ट स्टाफ जैसे फिजियोथेरेपिस्ट और फिजिकल ट्रेनर्स भी दिए जाते हैं।

खेलो इंडिया योजना (2016)

- खेलों इंडिया योजना की शुरुआत 2016 में हुई। इसने ग्रास रूट लेवल से प्रतिभाओं को सरकार तक पहुंचने के बीच सेतु का कार्य किया।
- मणिपुर में पहले विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। 20 खेलों को स्पोर्ट्स कोटे में सम्मिलित किया गया जैसे कि रोल बॉल, मलखम्ब इत्यादि। खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए खेलो को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया।
- जियो टैग, मोबाइल ऐप इत्यादि का निर्माण किया गया। स्कूल, कॉलेज में छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने के लिए खेलो इंडिया योजना के तहत वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं की शुरुआत भी की गई है जिन्हें खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का नाम दिया गया।
- ग्रामीण स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्थानों पर 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' प्रतियोगिताओं के आयोजन करवाए जा चुके हैं।
- महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ाने के लिए छोटे और जमीनी स्तर पर महिलाओं के लिए अलग से स्पोर्टस मीट की शुरुआत की गई।
- खेलों में महिलाओं और लड़कियों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, इसके लिए अब महिला और बाल विकास मंत्रालय ने खेल मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने का फैसला भी किया है।
- इतनी सारी योजनाओं के बावजूद अभी भी बहुत-सी ग्रामीण महिलाएं खेलों में आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। सामाजिक और पारिवारिक दबाव, धन का अभाव, प्रशिक्षण की कमी और कम जानकारी- सबका प्रभाव सीधे तौर पर महिलाओं पर पड़ा है।

ग्रामीण महिलाओं की खेलों में कम भागीदारी

- एक तरफ हमारे देश की महिलाएं ओलंपिक और पैरालम्पिक खेलों में नाम रोशन कर रही हैं वही बहुत-सी ग्रामीण महिलाएं हुनर होने के बावजूद अभी भी खेलों में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं।
- जिन वजहों से मुख्यत: ग्रामीण महिलाएं खेलों में हिस्सा नहीं ले पा रही हैं, वह इस प्रकार हैं सामाजिक कुरीतियां- पर्दा प्रथा, बच्चियों की छोटी उम्र में शादी और महिलाओं को घर से बाहर निकलने के कम अवसर आज भी ग्रामीण भारत का हिस्सा हैं।
- लड़कों लड़कियों में भेदभाव महिलाओं की पढ़ाई और खेलखूद पर विपरीत असर डालता है फलस्वरूप ज्यादातर महिलाओं की जिंदगी घर की चारदीवारी तक ही सीमित रह जाती है।

बच्चों की जिम्मेदारी-

- घर के कामकाज और बच्चों की जिम्मेदारी दो ऐसे कार्य हैं जो पूर्णत: ग्रामीण महिलाओं के हिस्से आते हैं और उनकी पूरी जिंदगी, उनकी सोच और उनकी मेहनत इन्ही के आसपास घूमती रहती है।

खेतीबाड़ी में भागीदारी-

- ग्रामीण भारत में खेतीबाडी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और इसे अक्सर उनके सशक्तीकरण से जोड़ा जाता है। खेतीबाड़ी में तो भागीदारी बढ़ी लेकिन घर और बच्चों से सम्बंधित जिम्मेदारियां आज भी उतनी ही हैं जिसके चलते उनकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनके पोषण का स्तर भी गिर रहा है।

पोषण की कमी-

- ग्रामीण परिवेश में बच्चों की परवरिश में आज भी भेदभाव होता है। बुढ़ापे की लाठी लड़कों को मान उन्हें बचपन से पौष्टिक भोजन दिया जाता है।
- बचपन से ही लड़कियों को भोजन कम खाने, कम सोने और कम शिकायत करने की सलाह दी जाती है। फलस्वरूप लड़कियां बचपन से ही संतुलित और पौष्टिक आहार से वंचित रहती हैं।

परिवार के साथ की कमी-

- बहुत बार बच्चियां स्कूलों में खेलों में हिस्सा लेती हैं और स्कूल वाले उनकी प्रतिभा देख परिवार को उनके बेहतर प्रशिक्षण की सलाह देते हैं।
- ऐसे में ग्रामीण परिवेश में गरीबी और सामाजिक डर से बहुत से अभिभावक बच्चियों को बेहतर प्रशिक्षण दिलवाने से घबराते हैं।

जानकारी का अभाव-

- समय के साथ थोड़ा-बहुत बदलाव आ रहा है। कई परिवार हैं जो बच्चियों को प्रशिक्षण दिलवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं।

सीमित सोच-

- बहुत से परिवार यह सोचकर बच्चियों को खेलों में आगे बढ़ने के मौके मिलने के बावजूद उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं।
- बच्चियों की प्रतिभाओं को नजरअंदाज कर छोटी उम्र से ही उन पर घर का काम सीखने और करने का दबाव बनाया जाता है।

खेल संबंधित सुविधाओं का अभाव-

- बहुत बार जब खेल संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है तो हुनर में निखार नहीं आ पाता और प्रतिभावान महिलाएं अपने कौशल नहीं दिखा पाती हैं।

आर्थिक दबाव-

- खेलों में हिस्सा लेना, प्रशिक्षण प्राप्त करना, खेल से जुड़ी वस्तुएं खरीदना- सब आर्थिक दबाव की तरफ इशारा करता है जो खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी का एक बड़ा कारण है।

सामाजिक दबाव-

- ग्रामीण परिवेश में महिलाओं के घर के बाहर निकलने से जुड़े बेतुके सामाजिक कायदे और नियम महिलाओं की तरक्की में रोड़ा बन रहे हैं।

अनजान परिस्थितियों से डर-

- कुछ इस तरह के सवाल महिलाओं और उनके परिवार वालों में भय पैदा करते है जोकि सीधे तौर पर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है।

बदलाव और सुझाव

- ग्रामीण महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने और उनके बेहतर प्रशिक्षण पर जोर देने के लिए जरूरत है कुछ बदलावों और सुझावों की जो परिस्थिति को बेहतर बना सकते हैं।
- महिलाओं को उनके परिवार का साथ मिले। इसके लिए राज्य सरकारें गांवों में विभिन्न खेलों पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करवा सकती हैं, पुरस्कार वितरण प्रक्रिया भी जिसका हिस्सा हो। ग्रामीण परिवेश की प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों के ऊपर लोकल अखबारों में लेख छपने से भी लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जा सकता है।
- प्रसिद्ध महिला खिलाड़ियों को बड़े मेलों आयोजनों में आमंत्रित कर सम्मानित किया जा सकता है। ऐसा करने से पूरे समाज में महिलाओं की खेलों में सफलतम भागीदारी पर एक अच्छा संदेश जाएगा।
- महिलाओं के लिए कल्याणकारी सरकारी नीतियां बनाना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। गांवों में खेल से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की आवश्यकता है।
- ग्रामीण परिवेश में समाज भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है। खिलाड़ी महिलाओं और उनके परिवार की समाज में इज्जत बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि महिला खिलाड़ियों के परिवार को पंचायत स्तर पर सम्मान और इनाम मिले।
- सामाजिक कुरीतियां और नकारात्मक पहलुओं को दूर करने के लिए गांवों में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा सकता है। महिला खिलाड़ियों के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए संतुलित और पौष्टिक भोजन के प्रबंध पर राज्य सरकारों को ध्यान देना होगा।
- स्थानीय स्तर पर महिलाओं हेतु विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करवायी जानी चाहिए ताकि अच्छी खिलाड़ियों की पहचान हो सके और उन्हें सम्मान भी मिले।
- वैज्ञानिक तकनीकी पर आधारित बेहतर खेल उपकरणों पर आधारित प्रशिक्षण से महिला खिलाड़ियों की प्रतिभाएं उभर कर आएंगी। ओलंपिक और पैरालम्पिक में भारतीय महिलाओं मुख्यत: ग्रामीण महिलाओं का प्रदर्शन इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि बदलाव की लहर चल पड़ी है, जो दूर तक जाएगी।
- ऐसी सरकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं जो वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य पर जोर दे रही हैं। बस जरूरत है तो व्यावहारिक और सामाजिक बदलाव की, जो महिलाओं के लिए आगे आने के द्वार खोलेगा।

देश में खेलों हेतु आधारभूत ढांचा

- टोक्यो ओलंपिक और पैरालम्पिक में भारतीय खिलाड़ियों को मिली अभूतपूर्व कामयाबी के बाद देश में खेलों को लेकर नया माहौल बन रहा है।
- वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल और एशियाई खेल होने हैं और टोक्यो की कामयाबी का असर इन खेलों में भी साफ नजर आना चाहिए।
- राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भारत पहले भी अच्छा प्रदर्शन करता आया है और अगले वर्ष इस प्रदर्शन में और इजाफा होना चाहिए।
- ओलम्पिक और पैरालम्पिक की कामयाबी से इन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देश खेलों के लिए आधारभूत सुविधाओं के मामले में अब भी बहुत पीछे है।
- खेल मंत्री ने 2028 के ओलम्पिक तक देश को टॉप 10 देशों में ले जाने का लक्ष्य रखा है इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत में बेहद तेजी से खेल अवसंरचना विकास समय की मांग है।
- कोरोना के कारण क्रिकेट के बहुचर्चित आईपीएल के पिछले दो संस्करण और टी-20 विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है जिससे देश में मौजूद क्रिकेट स्टेडियमों को बड़ा झटका लगा है।
- जिस देश में खेल अधिक लोकप्रिय होता है वहां पर आनंद या खुशी का स्तर भी बेहतर होता है। खेल जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार करता है।
- अब भारतीय खिलाड़ियों को मूलभूत सुविधाओं के लिए चिंता नहीं करनी पड़ रही है। इसके लिए उन्हें अपने खेल के दिनों में जूझना पड़ता था।
- ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई कर गए खिलाड़ियों को तो केंद्र सरकार 'टॉप्स' स्कीम के तहत 50-50 हजार रुपये का जेब खर्च देती थी, उनके लिए कोचों और सुविधाओं की पूरी व्यवस्था रहती थी और एक्सपोजर के लिए उन्हें विदेश भेजा जाता था लेकिन दूसरे खिलाड़ियों के पास इस तरह की कोई सुविधा नहीं थी।
- देश में अधिकतर स्कूलों की स्थिति यह है कि उनके पास साजो-सामान है लेकिन उनके पास ढंग के ग्राउंड नहीं हैं जहां उनके बच्चे अभ्यास कर सकें।
- मंत्रालय ने पहले चरण में आठ राज्यों में सरकार के स्वामित्व वाली खेल सुविधाओं को चिन्हित किया है।
- खेल मंत्रालय अपनी फ्लैगशिप योजना 'खेलो इंडिया' के तहत खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई) की स्थापना के लिए पूरी तरह तैयार है।
- पूरे देश में एक मजबूत खेल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के प्रयासों के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में ऐसा एक सेंटर चिन्हित किया जाएगा।
- पहले चरण में, मंत्रालय ने आठ राज्यों कर्नाटक, ओडिशा, केरल और तेलंगाना तथा अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नगालैंड जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सरकारी स्वामित्व वाले ऐसे खेल सुविधा केंद्रों की पहचान की है जिन्हें खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में अपग्रेड किया जाएगा।
- सरकार को कुल 15 खेल सुविधा केंद्रों के बारे में प्रस्ताव मिले थे जिन पर विचार के बाद इनमें से 8 केंद्रों को चुना गया। इनका चुनाव वहां प्राथमिकता वाले खेलों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं, आवश्यक बुनियादी अवसंरचना तथा वहां से बनकर निकले प्रतिभावान खिलाड़ियों के आधार पर किया गया।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश इन केंद्रों को चलाएंगे और इनकी क्षमता बढ़ाकर इन्हें विश्वस्तरीय खेल सुविधा केंद्रों में बदलने का काम करेंगे।
- हालांकि विशेषज्ञ कोच, सहायक कर्मचारियों, उपकरण तथा आधारभूत अवसंरचना के विकास के लिए कम पड़ने वाली वित्तीय जरूरतों को 'खेलो इंडिया' योजना के जरिए पूरा किया जाएगा।

हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स:

- 'खेलो इंडिया यूथ गेम्स' का आयोजन फरवरी 2022 में किया जाएगा।
- संक्षेप में, देश में शहरी क्षेत्रों में खेल सुविधाएं मौजूद हैं और माता-पिता भी बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे रहते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं का अभी खासा अभाव है हालांकि गांवों से बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों के आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। इस तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
- सायना नेहवाल, पीवी सिंधु, एमसी मैरीकॉम, साक्षी मलिक, शेफाली वर्मा जैसी खिलाड़ियों की कामयाबी ने महिला खिलाड़ियों के लिए नए रास्ते खोले हैं।
- सरकारों ने जिस तरह खिलाड़ियों पर धन वर्षा की है, उसने भी खिलाड़ियों को आगे आने और खेलों को अपना कॅरियर बनाने के लिए प्रेरित किया है।
- देश में खेलों को आगे बढ़ाना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि अगले साल राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ी 2018 के मुकाबले कितनी तरक्की कर पाते हैं।

'अतिथि देवो भव'

- किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा क्षेत्र के योगदान की अहम भूमिका होती है। साथ ही, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में सेवा क्षेत्र के योगदान के आधार पर ही विकास की प्रकृति और गुणवत्ता तय होती है।
- भारत के जीडीपी मे सेवा क्षेत्र का योगदान तकरीबन 55 प्रतिशत है और इसमें पर्यटन क्षेत्र की अहम हिस्सेदारी है।
- जीडीपी में पर्यटन क्षेत्र की हिस्सेदारी 5 प्रतिशत है और यह क्षेत्र प्रत्यक्ष और टिकाऊ रोजगार का भी जरिया है। भारत में 10 में से एक रोजगार पर्यटन क्षेत्र में पैदा होते हैं। साथ ही, इससे विदेशी मुद्रा भी हासिल होती है।
- कुल मिलाकर, पर्यटन क्षेत्र का असर बहुआयामी है क्योंकि इससे कई क्षेत्र जुड़े हैं और इन क्षेत्रों की पारस्परिक निर्भरता है। आर्थिक लाभ और सामाजिक-आर्थिक असर और समानता सुनिश्चित करने के नजरिए से देखा जाए, तो पर्यटन क्षेत्र सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला उद्योग है। पर्यटन के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर सम्मान हासिल है। इसकी वजह हमारे देश की समृद्ध संस्कृति और विरासत है।
- भारत के पर्यटन क्षेत्र की बुनियाद, यहां की गौरवशाली परंपराओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर आधारित है।
- भारत के पेड़-पौधे और जंगल, वास्तुशिल्प से संबंधित स्मारक, संगीत, चित्रकला, कला और शिल्प, नृत्य, अलग-अलग संस्कृतियां, परम्पराएं और त्यौहारों की वजह से इसे 'पर्यटकों के लिए स्वर्ग' माना गया है।
- जब कोई व्यक्ति भारत का भ्रमण करता है, तो उसे यहां पर कई तरह की संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। भारत के लोगों को अपनी संस्कृतियों को लेकर गर्व है। ये संस्कृतियां भारतीय पर्यटन की भी बुनियाद हैं।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का महत्व

- पर्यटन क्षेत्र एक तरह से उपभोग-आधारित आर्थिक क्षेत्र है और यहां पर काम करने वालों की काफी मांग है। यह क्षेत्र न सिर्फ पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष रोजगार मुहैया कराता है, बल्कि संबंधित/सहायक क्षेत्रों में भी अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
- पर्यटन क्षेत्र से विदेशी मुद्रा की कमाई होती है और भुगतान संतुलन से जुड़े घाटे को भी कम करने में मदद मिलती है। आर्थिक विकास में पर्यटन क्षेत्र की अहम भूमिका है। यह क्षेत्र रोजगार के नए ठिकाने बनाता है और अर्थव्यवस्था के लिए आय पैदा करता है।
- रोजगार पैदा करने और आय बढ़ाने में पर्यटन क्षेत्र का अहम योगदान है। यह आय के पुनर्वितरण और गरीबी कम करने में भी मददगार है।
- साथ ही, इससे शहरी-ग्रामीण असमानता और अमीर-गरीब के बीच की खाई को भी कम करने में मदद मिलती है।
- भारत में पर्यटन क्षेत्र की अहमियत से जुड़े कई पहलू हैं और इसका संबंध सामाजिक-आर्थिक विकास से भी है।
- भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में पर्यटन क्षेत्र के जरिए गरीबी हटाने व असमानता और बेरोजगारी कम करने जैसे लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं।
- यह क्षेत्र फेरी वाले, टैक्सी ड्राइवर, गाइड, फोटोग्राफर आदि के रूप में भी बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करता है।
- पर्यटन क्षेत्र ट्रैवल एजेंसी, आपूर्ति उद्योग, विज्ञापन एजेंसियां, खानपान उद्योग, मोटल, होटल और रेस्तरां के लिए भी अवसर उपलब्ध कराता है।
- पर्यटकों की मांग को पूरा करने के लिए नई इमारतों, होटल, मोटल और अतिथि गृह का निर्माण किया जा रहा है। इससे निर्माण उद्योग से जुड़े मजदूरों, इंजीनियरों, बढई, पेंटर, प्लंबर आदि के लिए भी रोजगार के अवसर मिलते हैं। पर्यटन क्षेत्र में रोजगार का दायरा बहुआयामी है। यह क्षेत्र युवा और उम्रदराज, पढ़े-लिखे और कम पढे-लिखे, पुरुष-महिला सभी के लिए बिना किसी भेदभाव के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।
- यह ऐसा क्षेत्र है जहां बड़े पैमाने पर श्रम की जरूरत पड़ती है, खासतौर पर कृषि क्षेत्र से पलायन करने वाले कर्मियों के लिए यहां गुंजाइश बन सकती है। यह क्षेत्र काफी हद तक कृषि क्षेत्र पर मौजूद दबाव को कम करने में सहायक है।
- किसी देश में पर्यटन क्षेत्र का विकास सीधे तौर पर वहां के आर्थिक विकास से जुड़ा होता है। यह बड़े पैमाने पर उद्यमिता संबंधी कौशल और पहले को भी बढ़ावा देता है।
- जीवन-स्तर को बेहतर बनाने, कलाओं और शिल्प कलाओं को बढ़ावा देने और पर्यावरण व सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी पर्यटन क्षेत्र योगदान कर रहा है।
- रोजगार सृजन और अतिरिक्त आय के अलावा यह क्षेत्र नए उत्पाद और सेवाओं के लिए भी अवसर उपलब्ध कराता है, जो किसी क्षेत्र/राज्य के सर्वांगीण विकास के लिहाज से काफी अहम हैं।
- यह क्षेत्र रोजगार के अलग-अलग माध्यमों को व्यापक स्तर पर आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। इससे कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने में भी मदद मिलती है। यह ऐसा क्षेत्र है जो अतिथियों और मेजबान, दोनों के लिए तमाम तरह की खुशियां लाता है और वैश्विक स्तर पर शांति और खुशी का माहौल बनाता है।

- दूसरे शब्दों में कहा जाए, तो पर्यटन क्षेत्र अलग-अलग तरह के पर्यटकों/घुमंतुओं के लिए बेहतर और यादगार अनुभव उपलब्ध कराने का कारोबार रेल जिसका सर्वांगीण विकास में प्रमुख योगदान है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास की स्थिति

- कोरोना महामारी ने वैश्विक स्तर पर पर्यटन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाया है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। भारत में इससे बड़े पैमाने पर लोगों की आजीविका प्रभावित हुई।
- मार्च, 2020 के बाद से लगभग 15-18 महीने तक पर्यटन गतिविधियों में जबर्दस्त गिरावट देखने को मिली।
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठा रही है और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, ताकि इस क्षेत्र को पटरी पर लाया जा सके।
- यह क्षेत्र लाखों-करोड़ों लोगों की आजीविका का माध्यम है, खासतौर पर गरीब और हाशिए पर मौजूद लोगों को इससे सहारा मिलता है।

'अतिथि देवो भव' जागरूकता की मिसाल

- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार ने 2005 में 'अतिथि देवो भव' नाम से सामाजिक जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य पर्यटकों से बेहतर व्यवहार सुनिश्चित करना और उनकी यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना है।साथ ही, लोगों को पर्यटकों से बेहतर व्यवहार के लिए प्रेरित करना है।
- अत:, 'अतिथि देवो भव' वास्तविक अर्थ में पर्यटकों के लिए बेहतर अनुभव मुहैया कराता है और इससे मेजबान और पर्यटकों के संबंधों को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अभियान के तहत आम लोगों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन उद्योग से जुड़े पक्षों पर फोकस किया गया है। इसके तहत पुलिस, आव्रजन अधिकारियों, ड्राइवरों, गाइड और अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।
- ये तमाम कर्मी सीधे तौर पर पर्यटकों से संवाद करते हैं। इस अभियान का मुख्य मकसद भारत को पर्यटन का पसंदीदा गंतव्य बनाना है। पर्यटन का बेहतर अनुभव काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि पर्यटकों की यात्रा और उनके ठहराव के दौरान स्थानीय लोग उनके साथ कितना सहयोग करते हैं।
- इस अभियान का मकसद नागरिकों को जवाबदेह बनाना है, ताकि हमारे देश की छवि पर आंच नहीं आए। हमारा बेहतर व्यवहार और जिम्मेदार तरीके से काम करने का अंदाज पर्यटन क्षेत्र को आगे बढ़ाएगा।
- पर्यटकों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए सरकार और अन्य पक्षों को जिम्मेदार तरीके से काम करना चाहिए।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का विश्लेषण

- रोजगार और आजीविका के विकास में पर्यटन क्षेत्र के योगदान को देखते हुए कहा जा सकता है कि विकास के एजेंडे में इस क्षेत्र की अहम भूमिका है।
- अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र के बहुआयामी असर और भूमिका को देखते हुए सरकार इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।

कोरोना महामारी और पर्यटन क्षेत्र

- कोरोना महामारी की वजह से पर्यटन क्षेत्र को तगड़ा झटका लगा। इस वजह से विश्व पर्यटन उद्योग को 2020 और 2021 के दौरान 4 खरब डॉलर का नुकसान हुआ।
- जहां तक भारतीय पर्यटन क्षेत्र का सवाल है, तो यहां भी कोरोना की वजह से कई स्तरों पर नुकसान देखने को मिला है, मसलन जीडीपी में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी कम हुई और इससे जुड़े प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार में भी गिरावट हुई। इसका असर लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ा।
- महामारी के कारण पूरी दुनिया मंदी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। हालांकि, भारत के पास फिर से उठ खड़ा होने की क्षमता है, जैसा कि अगस्त 2021 के बाद से देखने को मिल रहा है।
- कोरोना का प्रकोप बढ़ने के बाद ज्यादातर सामाजिक-आर्थिक गतिविधियां सुस्त पड़ गई थीं, लेकिन अब धीरे-धीरे ये फिर से पटरी पर लौट रही हैं। खासतौर पर पर्यटन क्षेत्र में यह रुझान देखने को मिल रहा है। यह निश्चित तौर पर एक सकारात्मक घटनाक्रम है।
- परिणामस्वरूप, कोरोना के प्रकोप के दौरान (मार्च 2020 से अगस्त 2021 के दौरान) फैली गरीबी, असमानता और बेरोजगारी में अब धीरे-धीरे कमी देखने को मिल रही है।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पहल

- कोरोना के दौरान हुए नुकसान से निपटने और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने कुछ योजनाओं की शुरुआत की है।
- मौजूदा अभियान 'आजादी का अमृत महोत्सव: आजादी के 75 साल बाद भारत के तहत कोरोना के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं।
- सरकार ने 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत कई योजनाओं की शुरुआत की जिनका मकसद पर्यटन का विकास है। पहले ही नए दौर के इनमें 'प्रसाद' और 'स्वदेश दर्शन' जैसी योजनाएं शामिल हैं।
- ये योजनाएं खासतौर पर पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू की गई हैं।

- 'स्वदेश दर्शन' योजना का मकसद पर्यटकों के अनुभव को बेहतर बनाना, अवसरों की उपलब्धता बढ़ाना और कम चर्चित ठिकानों का प्रचार करना शामिल हैं।
- पर्यटन मंत्रालय की 'प्रसाद' (तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान) योजना का मकसद तीर्थस्थलों और अन्य प्राचीन गंतव्यों को बढ़ावा देना है।
- पर्यटन विकास से जुड़ी अन्य योजनाएं इस तरह हैं- केंद्रीय एजेंसियों के लिए पर्यटन आधारभूत संरचना विकास, आय पैदा करने वाली पर्यटन परियोजनाओं के लिए गैप योजना, सेवाप्रदाता के लिए क्षमता निर्माण, घरेलू प्रचार और विज्ञापन (हॉस्पिटैलिटी समेत), विदेशों में प्रचार और विज्ञापन (मार्केटिंग विकास सहायता समेत), चैम्पियन सेवा क्षेत्र योजना, महिलाओं के लिए पर्यटन हेतु सुरक्षित स्थान आदि।
- पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों का संबंधित स्थलों के पर्यावरण और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू पर असर होता है। यह भी कहा जाता है कि हर गतिविधि के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। यह बात पर्यटन पर भी लागू होती है।
- अतः पर्यावरण पर पर्यटन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए 'सतत पर्यटन' की अवधारणा शुरू की गई है। सरकार पहले ही नए दौर के पर्यटन की शुरुआत कर चुकी है, जिसमें घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए खास तरह का पर्यटन शामिल है।
- सतत पर्यटन का मकसद 'मौसमी पर्यटन' को '365 दिनों के पर्यटन' में बदलना और विशेष अनुभवों के साथ नई श्रेणी के ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना है।
- खास तरह के पर्यटन में ये सभी शामिल हैं- समुद्री पर्यटन, जोखिमपूर्ण पर्यटन, फिल्मी पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, विरासती पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और सतत पर्यटन।

आगे की राह

- पर्यटक चाहे घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय शानदार आधारभूत संरचना और बेहतर अतिथि सेवाएं चाहते हैं। वे ऐसा अनुभव चाहते हैं, जो उन्हें वर्षों तक याद रहे। इस क्षेत्र का विकास करने के लिए सरकार हर तरह के उपाय कर रही है।
- हालांकि, पर्यटन नीति के ढांचे में बदलाव करने की जरूरत है, ताकि कोरोना के बाद के माहौल में पर्यटकों के लिए प्राथमिकताओं में बदलाव किया जा सके।
- हवाई सुविधा, रेलवे, सड़क और जल मार्ग जैसी आधारभूत संरचनाओं को और मजबूत बनाने की जरूरत है। साथ ही, पर्यटन क्षेत्र से जुड़े सुरक्षा पहलुओं को भी और बेहतर बनाना होगा। इस क्षेत्र में लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और स्थानीय स्तर पर इसे अंजाम दिया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा जा सके।
- सुरक्षा चुनौतियों से निपटने और पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए डिजिटल और कनेक्टिविटी नेटवर्क को भी मजबूत बनाना होगा। कोरोना महामारी की वजह से पिछले 15-18 महीनों से पर्यटन क्षेत्र को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।
- हालांकि, अब स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर केंद्र और राज्य सरकारें निजी पर्यटन उद्योग से जुड़े पक्षों के साथ मिलकर पर्यटन के विकास के लिए बेहतर रणनीति तैयार करती हैं, तो इससे निश्चित तौर पर भारत में सतत पर्यटन का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा।

Give The Best ★ Take The Best

Hindi/English Medium

निर्माण IAS

पढ़े उनसे जिन्होंने वास्तव में अधिकतम सफल अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन किया

OUR FACULTIES

K.D. Sir
इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, निबन्ध

Dharmendra Sir (Patanjali IAS)
एथिक्स

Dr. Rahees Singh Sir
इतिहास व अंतर्राष्ट्रीय संबंध

Rajeev Ranjan Singh Sir
भारतीय राजव्यवस्था, गवर्नेंस

Sameem Anwar Sir
भूगोल, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन

Dr. Adarsh Sir
भारतीय राजव्यवस्था, गवर्नेंस आंतरिक सुरक्षा

Dr. Khursheed Alam Sir
नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा एवं अभिरुचि

Shishir Sir
भारतीय अर्थव्यवस्था (Level-2)

Gautam Anand Sir
भारतीय समाज व सामाजिक न्याय

Dr. Raj Shekhar Sir
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

D.P.N. Singh Sir
सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी

Lokesh Tripathi Sir
भारतीय अर्थव्यवस्था (Level-1)

सामान्य अध्ययन

फाउण्डेशन बैच 2022-23

9 am Morning Batch

भारतीय राजव्यवस्था के साथ कक्षा प्रारम्भ...

By: Rajeev Ranjan Sir

04 January | 6:00 PM

21 January

English Medium
Exclusive Batch - 2022-23

996 1st Floor, Mukherjee Nagar (Near Gandhi Vihar Bandh) Delhi-09
PH.: 011-47058219, 9540676789, 9717767797